नई दिल्ली
मंगलवार
08 सितंबर 2026
वर्षः 13, अंकः 05
पृष्ठः 08, मूल्य 2 रु0

E-mail
story@sadbhawna.today
sadbhavnatoday@gmail.com
web: www.sadbhawna.today

हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

# सद्भावना टुडे

आवाज़ अधिकार की

DELHIN/2014/58158

दलीप ट्रॉफी फाइनलः ईशान किशन का तूफानी दोहरा...पेज-06

बिहार के बाढ़ प्रभावित वैशाली और सारण जिलों का...पेज-05

## एक नजर

### बेंगलुरु-चेन्नई एक्सप्रेसवे पर हुए सड़क हादसे में एक परिवार के चार लोगों की मौत

**कोलार,एजेंसी।** कर्नाटक के कोलार जिले के केजीएफ तालुक में दोड्डकारी के पास सोमवार तड़के हुए सड़क हादसे में एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई। हादसा बेंगलुरु-चेन्नई कॉरिडोर एक्सप्रेसवे पर हुआ। पुलिस के अनुसार, बेंगलुरु से चेन्नई जा रही टोयोटा कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में मैसूरु निवासी देवेंद्र कुमार (40), शारदम्मा (70), जिष्णु (15) और दीक्षिता (25) की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। वाहन में सवार चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। स्थानीय लोगों और पुलिस ने घायलों को तत्काल नजदीकी निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार जारी है। सूचना मिलने पर बेथमंगल पुलिस थाने के अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है।

### वित्त मंत्री ने आईएमएफ के उप प्रबंध निदेशक से की वैश्विक आर्थिक परिदृश्य पर चर्चा

**नई दिल्ली।** केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के उप-प्रबंध निदेशक नाइजेल क्लार्क से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के साथ-साथ भारतीय और वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के परिदृश्य पर चर्चा की। भारत के दौरे पर आये नाइजेल क्लार्क से केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में मुलाकात की। इस बैठक के दौरान सीतारमण और क्लार्क ने भारत-आईएमएफ संबंधों पर चर्चा की और दक्षिण एशिया क्षेत्रीय प्रशिक्षण एवं तकनीकी सहायता केंद्र (एसएआरटीटीएसी) को समर्थन देने में भारत की भूमिका की सराहना की। दोनों नेताओं ने दक्षिण एशिया क्षेत्रीय प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता केंद्र को समर्थन देने में भारत की भूमिका की सराहना की। दोनों पक्षों ने मैक्रो-इकोनॉमिक सहयोग को मजबूत करने, बेहतर नीतियों का समर्थन करने और क्षेत्रीय एवं वैश्विक आर्थिक मजबूती में योगदान देने के लिए भारत-आईएमएफ के बीच लगातार बातचीत और सहयोग के महत्व पर जोर दिया। इसके अलावा उन्होंने भारत और वैश्विक अर्थव्यवस्था के भविष्य के हालात पर भी चर्चा की। इसमें भारत की बदलती विकास दर और वैश्विक आर्थिक माहौल में हो रहे बदलावों के असर (जैसे भारत का व्यापार एजेंडा और हाल में हुए द्विपक्षीय व्यापार समझौतों सहित वैश्विक व्यापार प्रणाली में घटनाक्रम) शामिल थे। क्लार्क ने मौजूदा वैश्विक हालात में भारत के आर्थिक प्रदर्शन, मजबूती और विकास के ट्रैक रिकॉर्ड की सराहना की। इसके साथ ही उन्होंने फिस्कल कंसोलिडेशन (राजकोषीय मजबूती) और पश्चिम एशियाई संकट के बाद सरकार द्वारा उठाए गए समर्थनकारी कदमों के लिए भारत सरकार के प्रयासों को भी सराहा।

# सत्य निकेतन हादसे पर निगम की बड़ी कार्रवाई, उपायुक्त समेत पांच अधिकारी निलंबित

**नई दिल्ली,सद्भावना टुडे।** दिल्ली के सत्य निकेतन में हुए दर्दनाक हादसे के बाद दिल्ली नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दक्षिणी क्षेत्र के उपायुक्त समेत भवन विभाग से जुड़े पांच अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबित अधिकारियों में उपायुक्त, अधीक्षक अभियंता (भवन), अधिशासी अभियंता (भवन), सहायक अभियंता (भवन) और कनिष्ठ अभियंता (भवन) शामिल हैं। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने सोमवार को हादसे पर संज्ञान लेते हुए निगम की कार्रवाई की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सत्य निकेतन की घटना बेहद गंभीर और दुखद है तथा किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मामले की मजिस्ट्रेट जांच भी चल रही है।

महापौर ने बताया कि हादसे के समय संबंधित भवन खतरनाक श्रेणी में चिह्नित नहीं था, लेकिन भवन मालिक की ओर से बेसमेंट में कार्य किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि इस मामले में जिम्मेदारी तय करने के साथ-साथ भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए भी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने दिल्लीवासियों से अपील की कि वे अपने घरों या व्यावसायिक परिसरों में भवन की मूल संरचना के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ न करें। पिलर, बीम, कॉलम, स्लैब अथवा अन्य संरचनात्मक हिस्सों में बिना विशेषज्ञ सलाह और नियमानुसार अनुमति के बदलाव करना जान-माल के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। महापौर ने स्पष्ट किया कि भवन उप-नियमों का उल्लंघन करने अथवा चार मंजिल से अधिक भवन का निर्माण किए जाने पर नियमानुसार तत्काल कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी क्षेत्र में अनधिकृत निर्माण या अन्य गतिविधियां सामने आने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जाएगी और लापरवाही पाए जाने पर उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी सत्य निकेतन हादसे को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक नए दिशा-निर्देश तैयार करने के निर्देश दिए हैं। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने वाले भवनों के लिए संरचनात्मक सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य किए जाने की दिशा में कार्रवाई की जा रही है।

महापौर के अनुसार, इसका उद्देश्य व्यावसायिक गतिविधियों के कारण भवन पर पड़ने वाले अतिरिक्त भार अथवा अन्य प्रतिकूल प्रभावों का समय रहते आकलन करना और दुर्घटनाओं को रोकना है। दिल्ली नगर निगम के उत्तर-पश्चिम क्षेत्र में निर्माणाधीन और जर्जर भवनों की सुरक्षा को लेकर भी कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। सभी निर्माण स्थलों पर भवन मालिक और बिल्डर को स्वीकृत भवन योजना के अनुरूप ही निर्माण कार्य कराने तथा निर्धारित सुरक्षा मानकों और उपायों का अनिवार्य रूप से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। महापौर ने बताया कि निगम ने सभी संबंधित अधिकारियों को खतरनाक और जर्जर भवनों का ताजा सर्वेक्षण करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों से ऐसे भवनों की पहचान करने को कहा गया है, जिनसे नागरिकों के जीवन और संपत्ति को खतरा हो सकता है।

चिन्हित भवनों की स्थिति का गंभीरता से आकलन कर दिल्ली नगर निगम अधिनियम और अन्य लागू नियमों के तहत तत्काल कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि निगम का उद्देश्य केवल हादसा होने के बाद कार्रवाई करना नहीं, बल्कि संभावित दुर्घटनाओं की पहचान कर उन्हें पहले ही रोकना है। इसके लिए भवनों की निगरानी, अनधिकृत निर्माण के खिलाफ कार्रवाई और जर्जर भवनों की पहचान को प्राथमिकता दी जा रही है। महापौर ने कहा कि भवन सुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में भवन निर्माण और सुरक्षा संबंधी नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने तथा उल्लंघन पाए जाने पर बिना किसी दबाव के नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम नागरिकों की सुरक्षा एवं जनहित से जुड़े मामलों पर मिलकर काम कर रहे हैं। सत्य निकेतन जैसी घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिए निगम प्रशासन की ओर से सख्त कदम उठाए जा रहे हैं और नियमों का उल्लंघन करने वालों के साथ-साथ लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की जवाबदेही भी सुनिश्चित की जाएगी।

# महिला विधायकों को मजबूत करने से लोकतंत्र होगा मजबूतः ओम बिरला

**नई दिल्ली,एजेंसी।** लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि महिला विधायकों और महिला जनप्रतिनिधियों को सशक्त बनाने से लोकतंत्र और मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की सफलता के लिए संवाद, भागीदारी और विश्वास जरूरी है। महिला जनप्रतिनिधियों को विधायी प्रक्रिया, नीति निर्माण, कानून और बजट की बेहतर समझ विकसित कर अपने राज्यों और देश के विकास में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। बिरला सोमवार को राष्ट्रीय महिला आयोग की ओर से आयोजित दो दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यशाला के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

लोकसभा अध्यक्ष ने महिला विधायकों से सार्वजनिक सेवा को समावेशी शासन मजबूत करने का माध्यम बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि महिला नेतृत्व को मजबूत करने से शासन व्यवस्था में अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित होगी और लोकतांत्रिक संस्थाएं मजबूत होंगी। 'शी इज ए चेंजमेकर' पहल के तहत फरीदाबाद स्थित ताज सूरजकुंड रिजॉर्ट में 'महिला जनप्रतिनिधियों के लिए लैंगिक उत्तरदायी शासन' विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें देशभर से सौ से अधिक महिला विधायक और विधान परिषद सदस्य शामिल हुईं। इस मौके पर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजय रहाटकर ने कहा कि महिला विधायक सिर्फ अपने निर्वाचन क्षेत्रों की प्रतिनिधि नहीं हैं बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, तकनीक, सुरक्षा और सुशासन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर समाज की मजबूत आवाज भी हैं। उन्होंने कहा कि राजनीति और शासन में महिलाओं की भागीदारी से नीतियों में एक अलग और जरूरी दृष्टिकोण आता है। महिला जनप्रतिनिधियों का नेतृत्व समाज में व्यापक बदलाव का माध्यम बन सकता है। उन्होंने महिला विधायकों से अपने संवैधानिक अधिकारों और सार्वजनिक मंचों का प्रभावी इस्तेमाल करने की अपील की। रहाटकर ने कहा कि महिला जनप्रतिनिधियों को यह सुनिश्चित करने के लिए भी काम करना चाहिए कि उनके क्षेत्रों की महिलाएं अपने अधिकारों को समझें और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें।

कार्यशाला के पहले दिन नेतृत्व, विधायी कामकाज, सार्वजनिक नीति और लैंगिक उत्तरदायी शासन से जुड़े चार तकनीकी सत्र आयोजित किए गए। इन सत्रों में महिला विधायकों को शासन और जनप्रतिनिधित्व से जुड़े व्यावहारिक पहलुओं की जानकारी दी गई। साथ ही विभिन्न राज्यों की महिला जनप्रतिनिधियों को अपने अनुभव और सफल कार्यों को साझा करने का अवसर मिला। कार्यक्रम में ओडिशा विधानसभा की अध्यक्ष सुरमा पाढ़ी, छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, केरल की मंत्री बिंदु कृष्णा और के. ए. तुलसी, हरियाणा के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री राजेश नागर, पश्चिम बंगाल की आवास विभाग की राज्यमंत्री कलिता माझी और राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य सचिव सुदीप जैन सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

## सत्य निकेतन हादसाः मालिक दंपति और बेटा गिरफ्तार, बचाव अभियान खत्म, सात की मौत

**नई दिल्ली,एजेंसी।** दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के सत्य निकेतन में पांच मंजिला इमारत ढहने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मकान मालिक के परिवार के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने संपत्ति की मालकिन उर्मिला गुप्ता (75), उनके पति हरिराम गुप्ता (81) और बेटे महेश गुप्ता (52) को गिरफ्तार किया है। हादसे के बाद चलाए गए लंबे बचाव अभियान में मलबे के नीचे दबे कुल 12 लोगों को बाहर निकाला गया और अस्पताल पहुंचाया गया। इनमें से सात लोगों की मौत हो गई, जबकि पांच घायल अस्पताल में भर्ती हैं। घायलों में तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है।

हादसे के बाद विभिन्न एजेंसियों ने लगातार मलबा हटाने और दबे लोगों को तलाशने का अभियान चलाया। बचाव अभियान पूरा होने के बाद पुलिस ने साफ किया कि मलबे से कुल 12 लोगों को निकाला गया था। अस्पताल में सात लोगों ने दम तोड़ दिया। शव उनके परिजनों को सौंप दिए गए हैं। हादसे में जान गंवाने वालों में ज्यादातर युवा छात्र थे। मृतकों की पहचान अभिषेक (20), युवराज सोनी (20), पवन (17), अर्पित जहाज (19), अक्षत सिंह यादव (18) और 75 वर्षीय सुरिंदर सिंह के रूप में हुई है। एक मृतक की पहचान अभी नहीं हो सकी है। अभिषेक उत्तर प्रदेश के सोनभद्र का रहने वाला था, जबकि युवराज सोनी छत्तीसगढ़ के दुर्ग का निवासी था। 17 वर्षीय पवन उत्तर प्रदेश के औरैया का रहने वाला था। अर्पित जहाज मध्य प्रदेश के देवास और अक्षत सिंह यादव मध्य प्रदेश के कटनी का रहने वाला था। सभी पांचों युवा छात्र थे। वहीं, 75 वर्षीय सुरिंदर सिंह मजदूरी करते थे। सातवें मृतक की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। हादसे में घायल पांच लोगों का इलाज चल रहा है। इनकी पहचान असगर अली (30), नीरज बावा (19), आदित्य कुमार (19), नितिश चिब (19) और मोहम्मद अयान (18) के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक पांच घायलों में तीन की हालत गंभीर बनी हुई है। डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज किया जा रहा है।

## बागपत सड़क हादसे में मरने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़कर 12 हुई

**बागपत,एजेंसी।** उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में स्थित पूर्वी पेरीफेरल एक्सप्रेस-वे पर रविवार देर रात हुए सड़क हादसे में मरने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। 24 लोग घायल हैं, जिनका इलाज अलग-अलग अस्पतालों में चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर दुख प्रकट करते हुए मृतकों के परिजनों दो-दो लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क हादसे में घायलों को बेहतर इलाज मुहैया कराने के लिए जिला प्रशासन को आदेश दिए है। यह भी कहा कि इस दुख की घड़ी में सरकार पीड़ितों के साथ है, हर संभव मदद की जाएगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए मेरठ जिले के मंडल आयुक्त (कमिश्नर) भानु चन्द्र गोस्वामी और मेरठ के अपर पुलिस महानिदेशक (एडीजी) मेरठ भानु भास्कर ने घायलों का हालचाल लिया।

# क्षेत्रीय परिषद में अब हो रही जनकल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंगः अमित शाह

**नई दिल्ली,एजेंसी।** केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सोमवार को गोवा की राजधानी पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। अमित शाह ने कहा कि क्षेत्रीय परिषद अब विवाद समाधान की जगह जनकल्याण की योजनाओं के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग का साधन बन गई है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों के बीच अब कोई भी विवाद नहीं बचा है, यह एक बड़ी उपलब्धि है।

शाह ने यह भी कहा कि आज की बैठक में शामिल सभी मुद्दे मॉनीटरिंग के थे। राज्यों के बीच नदियों के कई विवाद भी क्षेत्रीय परिषद में हल किए गए हैं, बच्चों के कुपोषण, कम वजन पर भी हम क्षेत्रीय परिषदों में काम कर रहे हैं। आधार के पेनेट्रेशन को भी मॉनीटर कर रहे हैं और आयुष्मान भारत कार्ड को सफल करने के लिए भी यहां से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। नवीन न्याय संहिताओं के क्रियान्वयन और नशे के खिलाफ भारत की जंग को सफल करने के काम में भी पश्चिमी क्षेत्र को अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के कंप्यूटराइज़ेशन में भी महाराष्ट्र में 98 प्रतिशत और गुजरात में 92 प्रतिशत की दर से अच्छा काम हुआ है। उन्होंने कहा कि बनास डेयरी ने गोबरधन का जो मॉडल खड़ा किया है, उसे भी राज्य अपनाएं। बैठक में गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस और दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के प्रशासक प्रफुल्ल के. पटेल शामिल थे। केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों/ संघ राज्यक्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी परिषद की बैठक में भाग लिया। केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी साइबर अपराधों के खिलाफ रणनीति को लगातार 'प्रगति' में मॉनीटर कर रहे हैं। सभी राज्यों के अर्बन कोऑपरेटिव बैंक एफसीएफआरएस से जुड़ जाएं। म्यूल हंटर एआई से एकीकृत करने के लिए कोऑपरेटिव बैंकों को प्रेरित करने की ज़रूरत है। सभी सहकारी बैंक ढ्4सी से जुड़ जाएँ, इसके लिए भी हमें आगे बढ़ना होगा।

## रक्षा मंत्रालय ने एस्टोनिया के विवादित हथियार सौदे से जुड़ी भारतीय कंपनी से किसी तरह के लेन-देन से किया इनकार

**नई दिल्ली,एजेंसी।** रक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि एस्टोनिया में विवादित गोला-बारूद खरीद सौदे से जुड़ी भारतीय रक्षा कंपनी से उसका कोई संबंध या लेन-देन नहीं है। इस विवाद के चलते एस्टोनिया के रक्षा मंत्री हानो पेवकुर को पद से इस्तीफा देना पड़ा है। एस्टोनिया सरकार की यूक्रेन के लिए 155 मिलीमीटर तोप के गोला-बारूद की 7 करोड़ यूरो की खरीद से भारतीय कंपनी को जोड़कर सामने आई खबरों पर रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों की ओर से कंपनी को न तो कोई ऑर्डर दिया गया है और न ही कोई आपूर्ति की गई है।

मंत्रालय के सूत्रों ने सोमवार को कहा, 'रक्षा मंत्रालय से इसका कोई संबंध या लेन-देन नहीं है।' उन्होंने बताया कि नेको डिफेंस म्यूनिशंस कंपनी नागपुर स्थित एक इस्पात विनिर्माण समूह का हिस्सा है। सूत्रों के अनुसार कंपनी ने हाल ही में डाटासेल नाम की इटली की एक छोटी कंपनी का अधिग्रहण किया था, जो छोटे हथियारों और गोला-बारूद के निर्माण से जुड़ी है। समूह की रोमानिया में भी एक विनिर्माण इकाई है, जिसके पास एस्टोनिया को और उसके बाद यूक्रेन को आपूर्ति के लिए तोप के गोलों में विस्फोटक भरने का ठेका है। हालांकि मंत्रालय के सूत्रों ने स्पष्ट किया कि कंपनी को भारतीय सशस्त्र बलों से आपूर्ति का कोई आदेश नहीं मिला है। सूत्रों ने कहा कि कंपनी की वेबसाइट पर किए गए दावे के अनुसार, उसने राज्य पुलिस को आपूर्ति की हो सकती है। यह स्पष्टीकरण एस्टोनिया के रक्षा मंत्री हानो पेवकुर के इस्तीफे के बाद आया। यूरोपीय संघ की 'यूरोपीयन पीस फेसिलिटी' के तहत यूक्रेन के लिए एस्टोनिया द्वारा गोला-बारूद की खरीद को लेकर विवाद बढ़ने के बीच पेवकुर ने इस्तीफे की घोषणा की। यह विवाद 2024 में एस्टोनिया की रक्षा खरीद एजेंसी एस्टोनियाई सेंटर फॉर डिफेंस इन्वेस्टमेंट्स की ओर से यूक्रेन के लिए तोप के गोला-बारूद की खरीद के लिए दिए गए ठेकों से जुड़ा है। करीब 7 करोड़ यूरो की इस खरीद का भुगतान यूरोपीय संघ की यूरोपीयन पीस फेसिलिटी के जरिए किया गया था। उस समय एस्टोनिया ने बड़ी अग्रिम राशि का भुगतान किया था और रूस के साथ युद्ध के बीच यूक्रेन को तोप के गोला-बारूद की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा था।

# छह सीटों पर उपचुनाव छह अक्टूबर को, नतीजे नौ अक्टूबर को

**नई दिल्ली,एजेंसी।** चुनाव आयोग ने सोमवार को तमिलनाडु, पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल और असम में पांच विधानसभा एवं एक लोकसभा सीट पर उपचुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की। इन सीटों पर छह अक्टूबर को मतदान होगा और मतगणना नौ अक्टूबर को होगी।

आयोग के अनुसार चुनाव संबंधी गजट अधिसूचना 9 सितंबर को जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 16 सितंबर होगी। नामांकन पत्रों की जांच 17 सितंबर को होगी, जबकि उम्मीदवार 19 सितंबर तक नाम वापस ले सकेंगे। मतदान मंगलवार, छह अक्टूबर को और मतगणना शुक्रवार, छह अक्टूबर को होगी। पूरी चुनाव प्रक्रिया 11 अक्टूबर तक पूरी कर ली जाएगी। तमिलनाडु में मदुरांतकम (एससी) और धारापुरम (एससी) विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होगा। पुडुचेरी की थट्टनचावडी विधानसभा सीट पर मतदान होगा। पश्चिम बंगाल में रेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा

सीटों के लिए उपचुनाव होगा। वहीं, असम की नगांव लोकसभा सीट पर मतदान कराया जाएगा। इन सभी सीटों पर निर्वाचित प्रतिनिधियों के इस्तीफे के कारण रिक्तियां हुई हैं। मदुरांतकम सीट मारगाथम कुमारवेल के इस्तीफे के बाद, जबकि धारापुरम सीट पी. सत्यबामा के इस्तीफे के बाद रिक्त हुई। पुडुचेरी की थट्टनचावडी सीट एन. रंगासामी के इस्तीफे के बाद खाली हुई। पश्चिम बंगाल में रेजीनगर और नंदीग्राम सीटें क्रमशः हुमायूं कबीर और शुभेन्दु अधिकारी के इस्तीफे के बाद रिक्त हुईं। असम की नगांव लोकसभा सीट प्रद्युत बोरदोलोई के इस्तीफे के बाद खाली हुई। आयोग ने कहा कि जिन जिलों में इन चुनाव क्षेत्रों का पूरा या कोई हिस्सा आता है, वहां तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है।

यह उपचुनावों के संबंध में लागू निर्देशों के अधीन होगी। चुनाव आयोग ने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और विश्वसनीय मतदान सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। आयोग ने साफ-सुथरी और अद्यतन मतदाता सूची के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि वह 'शुद्ध और अद्यतन मतदाता सूची को स्वतंत्र, निष्पक्ष और विश्वसनीय चुनाव की आधारशिला मानता है। सभी छह चुनाव क्षेत्रों की मतदाता सूचियां पुनरीक्षण के बाद पहले ही अंतिम रूप से प्रकाशित की जा चुकी हैं। तमिलनाडु की मदुरांतकम और धारापुरम सीटों की अंतिम मतदाता सूची 23 फरवरी, 2026 को प्रकाशित हुई थी। पुडुचेरी की थट्टनचावडी सीट की मतदाता सूची 14 फरवरी को प्रकाशित की गयी थी। पश्चिम बंगाल में रेजीनगर और नंदीग्राम की अंतिम मतदाता सूची 28 फरवरी को, जबकि असम की नगांव लोकसभा सीट की अंतिम मतदाता सूची 10 फरवरी को प्रकाशित की गयी थी। चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में होने वाले इन उपचुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ने की संभावना है।

# मौसमी इन्फ्लुएंजा (एच1एन1) और डेंगू की रोकथाम को लेकर जागरूकता कार्यशाला का आयोजन

**सैफुल्लाह सिद्दीकी, वरिष्ठ पत्रकार**

**नई दिल्ली।** दिल्ली सरकार ने सोमवार को दिल्ली सचिवालय में मौसमी इन्फ्लुएंजा (एच1एन1) और डेंगू को लेकर जन-प्रतिनिधियों के लिए एक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया। इसमें विधायकों, पार्षदों और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को एक साथ लाकर मौसमी बीमारियों से निपटने और उनकी रोकथाम के लिए जमीनी स्तर पर तैयारियों को और अधिक मजबूत करना और समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करना था। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य जन-प्रतिनिधियों को एच1एन1 और डेंगू के लक्षणों, रोकथाम, समय रहते पहचान और उपचार के बारे में व्यावहारिक जानकारी देना है। साथ ही उन्हें अपने-अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य संबंधी सही जानकारी पहुंचाने और रोकथाम के उपायों के लिए नागरिकों को एकजुट करने में उनकी भूमिका पर भी विशेष जोर दिया गया। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि बीमारी की रोकथाम को केवल अस्पतालों और स्वास्थ्य कर्मियों तक सीमित नहीं रखा जा सकता है, इसके लिए समुदाय स्तर पर भी सक्रिय भागीदारी की जरूरत है। उन्होंने माननीय विधायकों और पार्षदों से स्वास्थ्य विभाग और फील्ड टीमों के साथ मिलकर काम करने का आग्रह किया, ताकि स्वास्थ्य संबंधी संदेश राजधानी के हर वार्ड, मोहल्ले और हर घर तक प्रभावी तरीके से पहुंच सकें।

स्वास्थ्य मंत्री ने एच1एन1 को लेकर बेवजह डरने के प्रति भी दिल्ली वासियों को आगाह करते हुए इस बात पर जोर दिया कि हर बुखार को एच1एन1 और डेंगू से नहीं जोड़ना चाहिए। आम वायरल संक्रमण से भी बुखार, खांसी और सर्दी-जुकाम हो सकता है। इसलिए नागरिकों को घबराने और खुद से बीमारी का अंदाज़ा लगाने (सेल्फ़-डायग्नोसिस) से बचना चाहिए और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मौसमी इन्फ्लूएंज़ा, इन्फ्लूएंज़ा वायरस से होने वाला सांस का संक्रमण है। यह हर उम्र के लोगों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन बच्चों, बुज़ुर्गों और पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे (कॉमोरबिडिटी) वाले लोगों पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है।

डेंगू को लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने विशेष रूप से मॉनसून और मॉनसून के बाद के समय में मच्छरों के पनपने की जगहों को खत्म करने के लिए लगातार कार्रवाई करने का आह्वान किया। डेंगू फैलाने वाला एडीज मच्छर रुके हुए पानी की थोड़ी सी मात्रा में जमा हुए पानी में भी पनप सकते हैं। इसलिए कूलर, गमले, छतों पर रखे बर्तन, पानी की टंकियां, बेकार पड़े सामान, टायर और ऐसी ही अन्य चीजें मच्छरों के पनपने की संभावित जगहें बन जाती हैं। उन्होंने जन-प्रतिनिधियों से अपील की कि वे अपने-अपने इलाके में लोगों को अपने आस-पास नियमित रूप से जांच कराने, पानी की टंकियों और बर्तनों को ढंककर रखने, पानी जमा करने वाले बर्तनों को हफ़्ते में कम से कम एक बार खाली करके साफ करने और ऐसी बेकार चीज़ों के साथ कचरे को हटाने के लिए प्रोत्साहित करें, जिनमें पानी जमा हो सकता है। उन्होंने जन-प्रतिनिधियों से यह भी आग्रह किया कि वे स्थानीय स्तर पर बचाव के प्रयासों में आरडब्ल्यूए, स्कूलों, मार्केट एसोसिएशन, कम्युनिटी संगठनों और सफाई टीमों को भी शामिल करें और कंस्ट्रक्शन साइट, ड्रेनेज, कचरे और पानी से जुड़ी जानकारी तुरंत जानकारी संबंधित विभाग को दें।

# ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को लेकर दिल्ली-एनसीआर में सुरक्षा बढ़ी

**शाहनवाज सैफ, सद्भावना टुडे**

**नई दिल्ली।** दिल्ली में आयोजित होने वाले आगामी 'ब्रिक्स शिखर सम्मेलन-2026' के मद्देनजर दिल्ली-एनसीआर की सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद करने की कवायद तेज हो गई है। सुरक्षा तैयारियों और ट्रैफिक प्रबंधन को पुख्ता करने के उद्देश्य से पूर्वी दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन स्थित डीसीपी कार्यालय परिसर में एक उच्चस्तरीय अंतरराज्यीय समन्वय बैठक आयोजित की गई।

इस बैठक की अध्यक्षता ईस्टर्न रेंज के संयुक्त पुलिस आयुक्त मिलिंद महादेव डुंबेरे ने की। बैठक में दिल्ली पुलिस की ओर से पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) ईस्ट राजीव कुमार, डीसीपी नॉर्थ-ईस्ट राहुल अलवाल, डीसीपी शाहदरा राजेंद्र प्रसाद मीणा के साथ-साथ नोएडा और गाजियाबाद के डीसीपी, दोनों जिलों के ट्रैफिक पुलिस अधिकारी, संबंधित सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) (ऑपरेशंस-ट्रैफिक) और सीमावर्ती थानों के एसएचओ मौजूद रहे। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद की सीमाओं पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सभी प्रमुख और संवेदनशील सीमा बिंदुओं पर 24 घंटे संयुक्त चेकिंग की जाएगी। अंतरराज्यीय अपराधियों पर नजर रखने और किसी भी संदिग्ध इनपुट से निपटने के लिए तीनों जिलों की पुलिस के बीच रियल-टाइम इंटेलिजेंस साझा की जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था के तहत होटल, गेस्ट हाउस, पीजी (पीजी), साइबर कैफे और अन्य संवेदनशील ठिकानों पर सघन तलाशी अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही इलाके में रह रहे नए किरायेदारों और घरेलू सहायकों का शत-प्रतिशत पुलिस सत्यापन सुनिश्चित किया जाएगा। हवाई सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ड्रोन, पैराग्लाइडर, हैंग-ग्लाइडर और अन्य रिमोट-कंट्रोल फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी अनाधिकृत उड़ान या संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सम्मेलन के दौरान विदेशी राष्ट्राध्यक्षों और वीआईपी मेहमानों के सुगम आवागमन को लेकर दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद की ट्रैफिक पुलिस मिलकर काम करेगी। आम जनता को जाम से बचाने और वाहनों की निर्बाध आवाजाही के लिए संयुक्त डायवर्जन तथा मार्ग प्रबंधन योजना लागू की जाएगी। भीड़ नियंत्रण, रूट सुरक्षा और किसी भी आकस्मिक आपात स्थिति से निपटने के लिए तत्काल प्रतिक्रिया टीमों को अलर्ट पर रखा गया है। सभी संबंधित एसीपी और थाना प्रभारियों को अपने जवानों की नियमित ब्रीफिंग करने और हाई अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक के अंत में अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि दिल्ली पुलिस, नोएडा पुलिस और गाजियाबाद पुलिस के बीच लगातार जमीनी तालमेल बना रहेगा, ताकि पूरे आयोजन को पूर्णत: सुरक्षित और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया जा सके।

# दिल्ली में रोकटोक को लेकर हुए विवाद में एक संगीतकार की हत्या, सभी आरोपित गिरफ्तार

**नई दिल्ली।** दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के किलोकरी गांव में देर रात शोर-शराबे और हुड़दंग का विरोध करने के मामले में एक संगीतकार की कथित हत्या की गई। पुलिस ने सभी आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है।

सनलाइट कॉलोनी थाना पुलिस के अनुसार यह घटना तब हुई जब संगीतकार सी. विक्रम सिंह के घर के सामने ढाबा कर्मी तथा डिलीवरी बॉय जमा होकर कथित तौर पर तेज आवाज में शोर और हुड़दंग कर रहे थे। उन्होंने घर से निकलकर उन्हें ऐसा करने से मना किया और शांति बनाए रखने को कहा लेकिन वे लोग नहीं माने और इस बात को लेकर दोनों के बीच नोकझोंक शुरू हुई। जिसके बाद आरोपितों ने उन पर लात-घूंसों से हमला किया। विक्रम गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके बेटे ने उन्हें पास के होली फैमिली अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। मृतक किलोकरी गांव के निवासी थे। फिलहाल पुलिस ने हत्या की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर नाबालिगों सहित सभी आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और रिपोर्ट तथा फॉरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।

# रेलवे टेंडर घोटाला के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप तय करने का फैसला फिर टला

**नई दिल्ली,एजेंसी।** दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने रेलवे टेंडर घोटाला के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लॉन्ड्रिंग आरोपितों के खिलाफ आरोप तय करने पर फैसला फिर टाल दिया। इसके पहले भी कोर्ट ने 29 अगस्त, 14 अगस्त, 31 जुलाई, 16 जुलाई, 9 जून, 22 मई और 6 मई को फैसला टाल दिया था। अब इस मामले पर 10 सितंबर को फैसला सुनाया जाएगा।

कोर्ट ने 13 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। 28 जनवरी 2019 को कोर्ट ने ईडी की ओर से दर्ज केस में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को भी नियमित जमानत दी थी। कोर्ट ने एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी थी। 19 जनवरी 2019 को कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दर्ज केस में लालू यादव को नियमित जमानत दी थी। कोर्ट ने 13 अक्टूबर 2025 को रेलवे टेंडर घोटाले के सीबीआई से जुड़े मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी

यादव समेत दूसरे आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने 17 सितंबर 2018 को ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। इस मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी समेत 16 लोगों को आरोपित बनाया गया है। ईडी ने जिन्हें आरोपी बनाया है उनमें लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मेसर्स लारा प्रोजेक्ट एलएलपी, सरला गुप्ता, प्रेमचंद गुप्ता, गौरव गुप्ता, नाथ मल ककरानिया,राहुल यादव, विजय त्रिपाठी, देवकी नंदन तुलस्यान,मेसर्स सुजाता होटल, विनय कोचर, विजय कोचर,राजीव कुमार रेलान और मेसर्स अभिषेक फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। लालू पर आरोप है कि उन्होंने रेल मंत्री रहते हुए रेलवे के दो होटलों को आईआरसीटीसी को ट्रांसफर किया और होटलों की देखभाल के लिए टेंडर जारी किये। रांची और पुरी के दो होटलों का आवंटन कोचर बंधु की कंपनी सुजाता होटल को ट्रांसफर किया गया था।

# डीयू कुलपति ने सत्य निकेतन हादसे पर जताई संवेदना, प्रिंसिपलों को नए हॉस्टल बनाने के निर्देश दिए

**नई दिल्ली।** दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने दक्षिणी परिसर के निकट सत्य निकेतन में रविवार को एक पीजी हॉस्टल की पांच मंचिला इमारत के गिरने के हादसे पर शोक व्यक्त किया। कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने सोमवार को प्रिंसिपलों की मीटिंग भी बुलाई और दुर्घटना में मृत विद्यार्थियों के प्रति संवेदना प्रकट की। कुलपति ने कहा कि बच्चों की जान का नुकसान दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए बहुत बड़ी क्षति है। यह घटना सबको झकझोरने वाली है। प्रो. योगेश सिंह ने कहा कि इस दुर्घटना में कुछ विद्यार्थियों की जान चली गई और कुछ को गंभीर चोटें आई हैं। उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदनाएं जताते हुए कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय हादसे के पीड़ितों की हर संभव मदद के लिए खड़ा है। कुलपति ने सभी प्रिंसिपलों से अपील की कि भविष्य में ऐसी घटना न हो इसके लिए निर्णय लेने की जरूरत हैं। इसके लिए जो भी प्रयास विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों की ओर से किए जा सकते हैं, हमें वो करने चाहिएं। कुलपति ने सभी प्रिंसिपलों से अपील की कि वे अपने-अपने कॉलेज में विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध आवासीय सुविधाओं की समीक्षा करें। मौजूदा छात्रावासों के साथ अगर उनके यहां कोई छात्रावास निर्माणाधीन है तो कोशिश करें कि उसे शीघ्रता से पूरा किया जाए और वह जल्दी से जल्दी विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध हो। सभी प्रिंसिपल अपने-अपने कॉलेजों में नए छात्रावासों के निर्माण की भी संभावनाएं तलाशें। संभावनाएं हैं, तो जल्द से जल्द उसके लिए योजना तैयार करें। इसके लिए उपलब्ध स्थान, सरकारी योजनाओं और संभावित सभी आवश्यकताओं व योजनाओं का आकलन करके नए छात्रावास निर्माण का कार्य शुरू करें। प्रो. योगेश सिंह ने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय विद्यार्थियों की हर संभव मदद के लिए खड़ा है।

# सत्य निकेतन हादसे पर कांग्रेस का धरना

**शबाना बेगम, सद्भावना टुडे**

**नई दिल्ली।** दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के सत्य निकेतन में पांच मंजिला पीजी/हॉस्टल इमारत ढहने की घटना को लेकर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने सोमवार को घटनास्थल पर धरना दिया। उन्होंने हादसे में मृत और घायल छात्रों के परिवारों को न्याय देने तथा जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। देवेन्द्र यादव ने आरोप लगाया कि सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना दिल्ली में व्याप्त कथित भ्रष्ट प्रशासनिक व्यवस्था का परिणाम है। उन्होंने सवाल उठाया कि करीब 50 वर्ष पुरानी पांच मंजिला इमारत के बेसमेंट में पानी भरने के बाद वहां बिना पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम के मरम्मत कार्य की अनुमति आखिर किसने दी ?

उन्होंने कहा कि हादसे की पूरी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और नगर निगम आयुक्त को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। यादव ने कहा कि जब तक दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं होती और मृतक एवं घायल छात्रों को न्याय नहीं मिलता, तब तक कांग्रेस का विरोध जारी रहेगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराए जाने पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि हर हादसे के बाद सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाने के बजाय अधिकारियों पर कार्रवाई की बात करती है, जबकि भाजपा ने भ्रष्टाचार खत्म करने और बेहतर प्रशासन देने का दावा किया

था। यादव ने कहा कि सत्य निकेतन क्षेत्र में पार्षद, विधायक, सांसद, मेयर, स्थायी समिति के अध्यक्ष और जोन अध्यक्ष सहित प्रमुख जनप्रतिनिधि भाजपा से जुड़े हैं। ऐसे में सरकार को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि क्या जिम्मेदार सत्ताधारी नेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली में प्रशासन और राजनीतिक नेतृत्व की जिम्मेदारी भाजपा के पास है, इसलिए राजधानी में लगातार हो रहे हादसों की जवाबदेही भी सरकार को लेनी चाहिए। देवेन्द्र यादव ने दावा किया कि भाजपा शासन के दौरान दिल्ली में इमारत ढहने की कई बड़ी घटनाएं सामने आई हैं। उन्होंने अप्रैल 2025 के मुस्तफाबाद हादसे, मई 2025 में पहाड़गंज में निर्माणाधीन इमारत के बेसमेंट हादसे, जुलाई 2025 के वेलकम इलाके की घटना, मई 2026 में सैदुलाजेब-साकेत में इमारत गिरने, जुलाई 2026 में रोहिणी हादसे और अब सत्य निकेतन की घटना का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इन घटनाओं में बड़ी संख्या में लोगों की जान गई है।

इसके अलावा मंगोलपुरी औद्योगिक क्षेत्र, संगम विहार और मालवीय नगर में आग की घटनाओं का हवाला देते हुए यादव ने दिल्ली सरकार पर हादसों को गंभीरता से नहीं लेने का आरोप लगाया। कांग्रेस अध्यक्ष ने सत्य निकेतन में चल रहे राहत एवं बचाव कार्य की गति पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यदि इमारत के मलबे में छात्र फंसे होने की आशंका है तो बचाव अभियान युद्धस्तर पर चलाया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि घटना के बाद एंबुलेंस और रेस्क्यू टीम के पहुंचने में देरी की शिकायतें सामने आईं, जिसकी भी जांच होनी चाहिए। यादव ने कहा कि यदि निर्माण और मरम्मत कार्य के दौरान निगम अधिकारियों ने समय रहते सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित कराया होता और नियमों के उल्लंघन पर रोक लगाई होती तो संभव है कि यह हादसा टाला जा सकता था। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच, जिम्मेदार लोगों की पहचान और पीड़ित परिवारों को उचित राहत एवं न्याय देने की मांग की।

## सत्य निकेतन हादसे के लिए जिम्मेदारों पर हो कार्रवाई, निगमायुक्त दें इस्तीफा : अभाविप

**नई दिल्ली।** अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) ने सत्य निकेतन हादसे के लिए जिम्मेदारों पर कार्रवाई करने और निगमायुक्त के इस्तीफे की मांग की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री डॉ. वीरेन्द्र सिंह सोलंकी ने सोमवार को आईटीओ कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में सत्य निकेतन में पीजी इमारत के हादसे को हृदयविदारक बताते हुए विद्यार्थियों की हुई मृत्यु की घटना पर शोक व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने कहा कि यह घटना दिल्ली में विद्यार्थी आवासों की सुरक्षा और प्रशासनिक निगरानी की गंभीर विफलता को उजागर करती है। उन्होंने कहा कि घटना के तुरंत बाद से ही अभाविप के कार्यकर्ता घटनास्थल पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य में प्रशासन तथा अन्य एजेंसियों के साथ सहयोग कर रहे हैं। डॉ. वीरेन्द्र सिंह सोलंकी ने बताया कि घटना की जानकारी के बाद अभाविप कार्यकर्ताओं ने एमसीडी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर प्रशासन की जवाबदेही तय करने, निगमायुक्त के इस्तीफे तथा प्रकरण में संलिप्त सभी व्यक्तियों के विरुद्ध सुसंगत आपराधिक धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर कठोर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया, जिसमें डूसू अध्यक्ष आर्यन मान सहित कई अभाविप कार्यकर्ता घायल हुए तथा 50 से अधिक कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। अभाविप ने मांग की कि घटना की उच्चस्तरीय एवं निष्पक्ष जांच कराकर पूर्ण जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। मकानमालिक, बिल्डर एवं ठेकेदार द्वारा किए गए निर्माण कार्यों की जांच के साथ यह भी स्पष्ट किया जाए कि मौजूदा भवन के नीचे बेसमेंट की खुदाई की अनुमति किसने दी, पीजी संचालन की अनुमति किस आधार पर दी गई और संबंधित एमसीडी अधिकारियों ने समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की।

# रोहिणी में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत, दो घायल

**नई दिल्ली।** बाहरी उत्तरी दिल्ली के रोहिणी सेक्टर-28 में सोमवार को एक तेज रफ्तार ट्रक ने कई वाहनों को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में गंभीर रूप से घायल बाइक सवार की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई जबकि दो अन्य लोग घायल हो गए। शाहबाद डेयरी थाना पुलिस के अनुसार दुर्घटना रोहिणी सेक्टर-28 स्थित राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) और भगवान अपार्टमेंट के पास हुई। तेज रफ्तार ट्रक ने एक ई-रिक्शा और बाइक को जोरदार टक्कर मारी जिससे दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। इसमें घायल तीन लोगों को तत्काल महर्षि वाल्मीकि अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उपचार के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक में प्रकाश विहार, सेक्टर-28 निवासी बलबीर सिंह (35) हैं। वहीं, प्रत्यक्षदर्शियों का आरोप है कि चालक शराब के नशे में धुत होकर बेहद लापरवाही और तेज गति से वाहन चला रहा था। उन्होंने उसे रुकने का इशारा भी किया लेकिन उसने वाहन की गति धीमी नहीं की और आगे चल रहे वाहनों को चपेट में ले लिया। शाहबाद डेयरी थाना पुलिस ने ट्रक चालक को मौके से दबोच लिया। आरोपी की पहचान 55 वर्षीय मुन्ना लाल के रूप में हुई है, जो उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है। चालक के नशे में होने के आरोपों की पुष्टि के लिए मेडिकल परीक्षण कराया गया है और मामले की विस्तृत जांच जारी है। पुलिस अन्य घायलों की पहचान और स्वास्थ्य स्थिति का विवरण जुटा रही है।

# एमसीडी, डीपीसीसी और पर्यावरण विभाग ने मनाया स्वच्छ वायु दिवस

**नई दिल्ली,एजेंसी।** दिल्ली नगर निगम (एमसीडी), दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) और दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग ने संयुक्त रूप से सोमवार को 'नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतरराष्ट्रीय दिवस' यानी स्वच्छ वायु दिवस मनाया। कार्यक्रम का आयोजन सुभाष नगर स्थित एमसीडी पश्चिमी क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय में किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य वायु गुणवत्ता में सुधार के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने के साथ पर्यावरण-अनुकूल और टिकाऊ प्रथाओं को प्रोत्साहित करना रहा। इस वर्ष कार्यक्रम में विशेष रूप से निर्माण एवं विध्वंस (सीएंडडी) स्थलों से होने वाले धूल प्रदूषण को कम करने और बायोमास जलाने के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता फैलाने पर जोर दिया गया।

कार्यक्रम में वार्ड समिति के अध्यक्ष हरीश ओबेरॉय, एमसीडी पश्चिमी क्षेत्र के उपायुक्त कर्नल विनोद अत्री, डीपीसीसी के वरिष्ठ पर्यावरण अभियंता संजय वत्स, डब्ल्यूआरआई इंडिया के क्लीन एयर प्रोग्राम के कार्यक्रम प्रबंधक संजर अली और पर्यावरण विभाग की वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी रंजना शर्मा सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। एमसीडी के मेंटेनेंस, भवन एवं डीईएमएस विभागों के अभियंताओं ने भी

कार्यक्रम में भाग लिया। स्थानीय बिल्डरों, वास्तुकारों और सफाई कर्मचारियों की सहभागिता ने वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए सरकारी एजेंसियों और सामुदायिक हितधारकों के बीच समन्वय की आवश्यकता को रेखांकित किया। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय परिसर में बड़े स्तर पर वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। इसका उद्देश्य स्थानीय हरित क्षेत्र को बढ़ावा देना और वायु गुणवत्ता में सुधार के साथ शहरी जैव-विविधता के संरक्षण को प्रोत्साहित करना था। इस दौरान विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। विद्यार्थियों ने जागरूकता रैली निकालकर वायु प्रदूषण कम करने और पर्यावरण-अनुकूल आदतें अपनाने का संदेश दिया।

इस अवसर पर हरीश ओबेरॉय ने कहा कि अपने आसपास की हवा को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी सभी की है। उन्होंने कहा कि निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण को मजबूत करने और बायोमास जलाने में कमी लाने से लोगों के स्वास्थ्य और दिल्ली के भविष्य की रक्षा की जा सकती है। उन्होंने स्वच्छ हवा के लिए सामूहिक रूप से प्रभावी कदम उठाने की प्रतिबद्धता दोहराई। उपायुक्त कर्नल विनोद अत्री ने कहा कि वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार, उद्योग, स्थानीय समुदायों और नागरिकों को निरंतर मिलकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि स्वच्छ वायु दिवस का आयोजन स्वच्छ हवा और स्वस्थ एवं हरित दिल्ली के निर्माण के लिए सभी हितधारकों की साझा जिम्मेदारी का संदेश देता है। कार्यक्रम में वक्ताओं ने निर्माण एवं विध्वंस स्थलों के बेहतर प्रबंधन के माध्यम से धूल उत्सर्जन को नियंत्रित करने और बायोमास जलाने के खिलाफ प्रभावी प्रवर्तन की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बायोमास जलाना मौसमी वायु प्रदूषण बढ़ाने वाले प्रमुख कारकों में शामिल है। साथ ही जनस्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सतत शहरी विकास तथा स्वच्छ वायु से जुड़े नियमों का प्रभावी एवं कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने की अपील की।

# लॉरेंस बिश्नोई के करीबी तक पहुंची क्राइम ब्रांच, 45 साल का कारोबारी गिरफ्तार

**नई दिल्ली।** अंतरराष्ट्रीय हथियार तस्करी और आतंकी गठजोड़ के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। क्राइम ब्रांच की एंटी-एक्सटॉर्शन एंड किडनैपिंग सेल (एआरएससी) ने कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई सिंडिकेट से जुड़े एक अहम सहयोगी और 45 वर्षीय कारोबारी ऋषभ कपूर को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, ऋषभ कपूर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के करीबी सहयोगी दीपक नंदा उर्फ दीपक खत्री उर्फ मामा का करीबी है। आरोपी की निशानदेही पर ऑस्ट्रिया में बनी एक ग्लॉक पिस्टल और पांच जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। यह कार्रवाई क्राइम ब्रांच में दर्ज प्राथमिकी पर आगे की जांच के दौरान की गई। यह मामला शाहबाज अंसारी से जुड़े अंतरराष्ट्रीय हथियार तस्करी और आतंकी मॉड्यूल से संबंधित है। आरोपी दीपक नंदा से पूछताछ और उसके खुलासे के आधार पर पुलिस ने ऋषभ कपूर तक पहुंच बनाई। उसे 3 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने बताया कि इस मामले में अब तक कुल 20 आरोपितों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनके कब्जे से 33 अत्याधुनिक विदेशी हथियार और गोला-बारूद बरामद हुआ है। बरामद हथियारों में दो सब-मशीन गन और 368 जिंदा कारतूस भी शामिल हैं। इस मामले में 18 गिरफ्तार आरोपियों और फरार आरोपी शाहबाज अंसारी के खिलाफ 24 अगस्त को राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष यूएपीए अदालत में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। ऋषभ कपूर वसंत विहार का रहने वाला है और कारोबारी होने के साथ फाइनेंसर का काम भी करता है। दिल्ली-एनसीआर में वह बाउंसर उपलब्ध कराने की एजेंसी भी चलाता है।

## एक नजर

### स्वतंत्र भारद्वाज ने गिरफ्तारी को दी चुनौती, दिल्ली हाई कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर

**नई दिल्ली।** जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान एक प्रदर्शनकारी के पिता पर हमला कर घायल करने के आरोपित स्वतंत्र भारद्वाज ने दिल्ली उच्च न्यायालय (हाई कोर्ट) में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की है। हाई कोर्ट आज ही इस याचिका पर सुनवाई करेगा। स्वतंत्र भारद्वाज की ओर से पेश वकील ने आज चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन करते हुए कहा कि स्वतंत्र भारद्वाज तीन दिनों से हिरासत में है। यह गैरकानूनी है। उन्होंने इस याचिका पर आज ही सुनवाई करने की मांग की, जिसके बाद कोर्ट ने आज ही सुनवाई करने का आदेश दिया। स्वतंत्र भारद्वाज को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से 4 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। स्वतंत्र की गिरफ्तारी तब हुई जब उसने एक पॉडकास्ट में इस बात को स्वीकार किया कि उसने एक प्रदर्शनकारी छात्रा के पिता के सिर पर हमला किया। इस पॉडकास्ट के बाद कॉकरोच जनता पार्टी और कुछ राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने संसद मार्ग थाने पर प्रदर्शन किया था। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि जब स्वतंत्र भारद्वाज ने खुद ही पॉडकास्ट पर आरोप कबूल किया है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। इसके बाद स्वतंत्र भारद्वाज गिरफ्तार किया गया। उसके खिलाफ पॉक्सो कानून और एससी-एसटी एक्ट की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज किया गया है।

### नूंह में गरीब लड़कियों की शादी के नाम पर ठगी का आरोपी दो साल बाद गिरफ्तार

**नूंह।** गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता, मोटरसाइकिल, फर्नीचर और घरेलू सामान उपलब्ध कराने का झांसा देकर कथित ठगी करने के मामले में रोजकामेव थाना पुलिस ने एक आरोपी को करीब दो वर्ष बाद गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान आसिफ निवासी गांव घासेड़ा, थाना सदर नूंह के रूप में हुई है। आरोपी के खिलाफ वर्ष 2024 में थाना रोजकामेव में दर्ज दो अलग-अलग मामलों में उसकी भूमिका सामने आई थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी गिरफ्तारी से बच रहा था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने सोमवार को बताया कि पहला मामला गांव उदाका निवासी मुबारिक की शिकायत पर दर्ज किया गया था।

शिकायत में आरोप लगाया गया था कि आरोपी और उसके साथियों ने बेटियों की शादी में मदद दिलाने का भरोसा देकर मुबारिक और उसके भाई कय्यूम से लाखों रुपये लिए। आरोप है कि उन्हें मोटरसाइकिल, फर्नीचर, घरेलू सामान और कन्यादान राशि उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन वादे के अनुसार पूरी सहायता नहीं दी गई। इसी प्रकार दूसरे मामले में भी बेटियों की शादी में सहायता उपलब्ध कराने के नाम पर लोगों से रकम लेने और बाद में उन्हें टालमटोल कर कथित रूप से ठगी करने के आरोप लगाए गए थे। जांच के दौरान पुलिस ने गिरोह से जुड़े अन्य आरोपियों के खिलाफ भी कार्रवाई की थी। कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में चालान पेश किया जा चुका है, जबकि कुछ आरोपी जमानत पर हैं। पुलिस के अनुसार दोनों मामलों की जांच के दौरान आसिफ की भूमिका सामने आई। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी से पूछताछ कर मामले से जुड़े तथ्यों की जानकारी जुटाई। आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन के न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।

### इंदिरापुरम से वैशाली तक 84 भूखंडों की नीलामी आज, पहली बार मिक्स लैंड यूज प्लॉट भी शामिल

**गाजियाबाद।** जीडीए की विभिन्न योजनाओं में 84 भूखंडों की आज हिंदी भवन सभागार में नीलामी होगी। इनमें सबसे अधिक 62 भूखंड इंदिरापुरम और इसकी विस्तार योजना के हैं। पहली बार पांच मिक्स लैंड यूज भूखंड भी नीलामी में शामिल किए गए हैं। 18 मीटर चौड़ी सड़क पर स्थित इन भूखंडों का इस्तेमाल स्वीकृत नक्शे के आधार पर आवासीय और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जा सकेगा। नीलामी में 120 से लेकर सात हजार वर्गमीटर तक के भूखंड शामिल हैं। इनमें आवासीय, व्यावसायिक, दुकान, होटल, क्योस्क, ग्रुप हाउसिंग समेत विभिन्न श्रेणी के भूखंड हैं। मधुबन बापूधाम में औद्योगिक, इंद्रप्रस्थ योजना में ग्रुप हाउसिंग और वैशाली, कौशांबी, कर्पूरीपुरम, आंबेडकर रोड डिस्ट्रिक्ट सेंटर व यूपी बार्डर में भी अलग-अलग श्रेणी के भूखंड रखे गए हैं। इनमें स्कूल, अस्पताल, नर्सिंग होम और हेल्थ सेंटर के भूखंड भी शामिल हैं। उक्त जानकारी देते हुए जीडीए के अपर सचिव प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि नीलामी सुबह 11 बजे आरंभ होगी। सबसे अधिक बोली लगाने वाले को भूखंड आवंटित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि भूखंड बिक्री की मांग को देखते हुए प्राधिकरण को बेहतर आय की उम्मीद है, जिसको शहर के विकास कार्य पर खर्च किया जाएगा।

# गाजियाबाद में जीडीए की 10 संपत्तियां नीलाम, 105 करोड़ रुपये से अधिक मिला राजस्व

**गाजियाबाद,एजेंसी।** लोहिया नगर स्थित हिंदी भवन में सोमवार को गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की संपत्तियों की नीलामी में निवेशकों ने रुचि दिखाई। 105.65 करोड़ रुपये में जीडीए की दस संपत्तियों की नीलामी हुई है। इन रुपयों का इस्तेमाल शहर के विकास कार्य में किया जाएगा। नीलामी में इंदिरापुरम विस्तार योजना का एक आवासीय भूखंड शामिल रहा। इंदिरापुरम के ज्ञानखंड-3 में एक दुकान और एक आवासीय भूखंड तथा ज्ञानखंड-2 में एक आवासीय भूखंड की बोली लगी।

इसके अलावा कोयल एनक्लेव में ग्रुप हाउसिंग और प्राइमरी स्कूल के भूखंड नीलाम हुए। वैशाली सेक्टर-3 में सामुदायिक केंद्र का भूखंड, यूपी बॉर्डर (चिकंबरपुर) योजना में दो दुकान भूखंड

और ब्रज विहार में निर्मित सामुदायिक केंद्र भी नीलामी का हिस्सा रहे। नीलामी से गाजियाबाद में आवासीय, वाणिज्यिक और संस्थागत गतिविधियों के लिए बढ़ती मांग का संकेत मिला है।

जीडीए उपाध्यक्ष नंद किशोर कलाल का कहना है कि नीलामी प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष और प्रतिस्पर्धात्मक तरीके से पूरा कराया गया। प्रतिस्पर्धी बोलियों के माध्यम से संपत्तियों का बेहतर मूल्य हासिल करने का प्रयास किया गया। इससे प्राधिकरण के राजस्व में बढ़ोतरी के साथ शहर के विकास कार्यों को भी आर्थिक मजबूती मिलेगी। नीलामी से प्राप्त राजस्व का उपयोग सड़क, आधारभूत ढांचे, नागरिक सुविधाओं और अन्य विकास परियोजनाओं को गति देने में किया जाएगा।

## गाजियाबाद में महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनी महिला वालंटियर फोर्स, 24 थानों से 591 महिलाएं जुड़ीं

**गाजियाबाद।** महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण को लेकर कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस ने सामुदायिक भागीदारी की दिशा में एक प्रयास किया है। पुलिस की ओर से महिला वालंटियर फोर्स (एमवीएफ) का गठन किया गया है। इसके लिए कमिश्नरेट के 24 थाना क्षेत्रों से कुल 591 महिलाओं को चिह्नित किया गया है। यह महिलाएं पुलिस और समाज के बीच सेतु की भूमिका निभाते हुए महिला सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को प्रभावी तरीके से पुलिस तक पहुंचाने में सहयोग करेंगी। एमवीएफ में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय और अनुभवी महिलाओं को जोड़ा जा रहा है। इनमें डाक्टर, अधिवक्ता, शिक्षिकाएं, समाजसेवी, गृहिणियां, काउंसलर, उद्यमी और अन्य क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाएं शामिल की जा रही हैं। अधिकारियों के मुताबिक इसका उद्देश्य केवल शिकायतों को पुलिस तक पहुंचाना नहीं, बल्कि स्थानीय स्तर पर महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल तैयार करने में सामुदायिक भागीदारी बढ़ाना है। महिला वालंटियर्स महिलाओं और बालिकाओं से संबंधित समस्याओं को पुलिस तक पहुंचाने में मदद करेंगी। साथ ही महिला सुरक्षा और अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने, जरूरतमंद महिलाओं को सरकारी योजनाओं और सहायता तंत्र की जानकारी देने तथा आवश्यकता पड़ने पर काउंसलिंग और सामाजिक सहयोग उपलब्ध कराने में सहायता करेंगी।

# गुरुग्राम में सैनिटेशन नोडल असिस्टेंट करेंगें स्वच्छता की निगरानी

**गुरुग्राम,एजेंसी।** नगर निगम गुरुग्राम ने शहर की स्वच्छता व्यवस्था को दुरुस्त बनाने तथा सफाई संबंधी शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए सभी 36 वार्डों में सहायक सफाई निरीक्षकों को सैनिटेशन नोडल असिस्टेंट (एसएनए) नियुक्त किया गया है। इस संबंध में निगमायुक्त द्वारा आदेश जारी किया गया है। सोमवार को जारी आदेश के अनुसार वार्डवार नियुक्त किए गए सैनिटेशन किया नोडल असिस्टेंट अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित निरीक्षण, स्वच्छता कार्यों की निगरानी और सफाई संबंधी कमियों के त्वरित समाधान के लिए जिम्मेदार होंगे। इसका उद्देश्य फील्ड स्तर पर स्वच्छता व्यवस्था की लगातार मॉनिटरिंग करते हुए नागरिकों को बेहतर सफाई व्यवस्था उपलब्ध कराना है।

एसएनए द्वारा अपने संबंधित वार्डों में विशेष रूप से सफाई संबंधी कार्यों की नियमित निगरानी की जाएगी। इनमें गार्बेज वर्नेबल पॉइंट्स (जीवीपी) से कूड़े की हटाना, डोर-टू-डोर कूड़ा उठान एवं संबंधित स्वच्छता सेवाओं की निगरानी, सडक़ों, गलियों एवं सार्वजनिक स्थानों की सफाई सुनिश्चित करना तथा वार्ड में सामने आने वाले अन्य स्वच्छता संबंधी मुद्दों, शिकायतों एवं कमियों पर कार्रवाई करवाना शामिल है। नियुक्त सैनिटेशन नोडल असिस्टेंट को अपने वार्ड में नियमित फील्ड निरीक्षण करना होगा। निरीक्षण के दौरान सामने आने वाली स्वच्छता संबंधी कमियों को संबंधित फील्ड स्टाफ अथवा एजेंसी के संज्ञान में लाकर उनका समाधान सुनिश्चित कराया जाएगा।

आदेश के अनुसार, सभी फील्ड निरीक्षण एमसीजी इंस्पेक्शन ऐप पर अनिवार्य रूप से दर्ज किए जाएंगे। इसमें निरीक्षण का विवरण, सामने आई कमियां और की गई कार्रवाई को रिकॉर्ड किया जाएगा। एसएनए विभिन्न माध्यमों से प्राप्त स्वच्छता संबंधी शिकायतों की भी नियमित निगरानी करेंगे। इसके अलावा अधिकारियों, आरडब्ल्यूए, नागरिक प्रतिनिधियों तथा अन्य वैध माध्यमों से प्राप्त शिकायतों पर भी कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी। जीवीपी, डोर-टू-डोर कूड़ा उठान, सडक़ सफाई और अन्य स्वच्छता संबंधी शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर हल करवाने के निर्देश दिए गए हैं। गंभीर, बार-बार सामने आने वाली अथवा लंबित शिकायतों को संबंधित संयुक्त आयुक्त के संज्ञान में लाने की व्यवस्था भी की गई है।

# दुनिया की 200 नस्लों में से 81 गाजियाबाद में, लैब्राडोर सबसे पसंदीद

**अशोक कुमार, सद्भावना टुडे**

**गाजियाबाद।** अमेरिकन केनेल क्लब के अनुसार विश्व में 200 नस्ल के कुत्ते हैं। इनमें से गाजियाबाद में कुल 81 नस्ल के कुत्ते पाले जा रहे हैं। कुल 81 में से 79 विदेशी नस्ल के कुत्ते हैं। शहर में कुल 7,040 कुत्ते वैध रूप से पाले जा रहे हैं। गाजियाबाद के लोगों की पहली पसंद लैब्राडोर रिट्रीवर हैं। शहर में कुल 1,594 लैब्राडोर कुत्ते पाले जा रहे हैं। इसके बाद जर्मन शेफर्ड के 912 और इंडियन डाग यानी देसी 757 कुत्ते पाले जा रहे हैं। नगर निगम में पालतू कुत्ते का पंजीकरण कराना जरूरी है। इसके लिए नगर निगम की ओर से डाग लाइसेंस की आनलाइन सुविधा उपलब्ध है। पंजीकरण के साथ कुत्ते का वैक्सीनेशन कराया जाना जरूरी है। कुत्ते को बाहर ले जाते समय उसे नियंत्रण में रखना होता है।

हाल में पालतू कुत्तों के काटने की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए नगर निगम ने कुत्ते पालने के नियम सख्त किए हैं। उप मुख्य पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी डा. अनुज ने बताया कि नगर निगम में 1,594 लैब्राडोर कुत्ते पंजीकृत हैं। इसकी लोकप्रियता का बड़ा कारण इसका स्वभाव माना जाता है। लैब्राडोर सामान्य तौर पर लोगों के साथ आसानी से घुलता-मिलता है और प्रशिक्षण लेने में सक्षम होता है। शहर में गोल्डन रिट्रीवर के 711 और बीगल के 523 कुत्ते पंजीकरण हैं। महंगी नस्लों की

कीमत केवल नस्ल से तय नहीं होती। उसकी उम्र, नस्ल की शुद्धता, माता-पिता की ब्लडलाइन, स्वास्थ्य, प्रमाणपत्र और ब्रीडर के आधार पर कीमत काफी बदल सकती है। तिब्बतन मैस्टिफ की कीमत करीब पांच से 10 लाख रुपये तक बताई जाती है। समोयेड करीब 60 हजार से तीन लाख रुपये और अकिता करीब डेढ़ से चार लाख रुपये तक कीमत के कुत्ते पाले जा रहे हैं। चाउ चाउ की कीमत भी करीब एक से तीन लाख रुपये तक बताई जाती है। गाजियाबाद में तिब्बतन मैस्टिफ के आठ, समोयेड के तीन, अकिता के तीन और चाउ चाउ के 17 कुत्ते पाले जा रहे हैं। गाजियाबाद में पाले जा रहे ताकतवर और मजबूत शरीर वाली कई नस्लें शामिल हैं। इनमें राटवाइलर, जर्मन शेफर्ड, डाबरमैन, अमेरिकन स्टैफर्डशायर टेरियर, मास्टिफ, बुलमास्टिफ, डोगो अर्जेंटीनो और बेल्जियन मेलिनोइस प्रमुख हैं। राटवाइलर के 182 कुत्ते हैं। डोबरमैन तेज, चौकन्ना और सुरक्षा के लिए उपयोगी माना जाता है। बेल्जियन मेलिनोइस अपनी फुर्ती, तेज सीखने की क्षमता और काम करने की ऊर्जा के लिए दुनिया की सुरक्षा एजेंसियों में पसंद किया जाता है। जर्मन शेफर्ड और बेल्जियन मेलिनोइस जैसी नस्लें पुलिस और सेना के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। पुलिस जर्मन शेफर्ड और बेल्जियन मेलिनोइस का इस्तेमाल गश्त, सुरक्षा और विस्फोटक या नशीले पदार्थ खोजने जैसे कामों में किया जाता है। लैब्राडोर को भी गंध पहचानने वाले कामों में इस्तेमाल किया जाता है।

# यूजीसी नियमों के खिलाफ प्रदर्शन की इजाजत पर 14 सितंबर तक फैसला ले दिल्ली पुलिसः हाई कोर्ट

**नई दिल्ली।** दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस से कहा है कि वो जंतर-मंतर पर आरक्षण और यूजीसी के नियमों के खिलाफ प्रदर्शन करने की इजाजत देने पर 14 सितंबर तक फैसला ले। जस्टिस अमित महाजन की बेंच ने ये आदेश दिया।

क्षत्रिय करणी सेना 20 सितंबर को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करना चाहती है। कोर्ट ने क्षत्रिय करणी सेना से कहा है कि वो पुलिस को अपना आवेदन दें। पुलिस 14 सितंबर तक उस पर फैसला करेगी और आपको अपने फैसले की जानकारी देगी। पुलिस जो भी शर्त लगाना चाहे, लगा सकती है। इससे पहले, करणी सेना ने 6 सितंबर को प्रदर्शन की इजाजत मांगी थी लेकिन पुलिस ने ब्रिक्स सम्मेलन की तैयारियां का हवाला देते हुए इससे इनकार कर दिया था। उच्च न्यायालय ने 3 सितंबर को याचिकाकर्ता से कहा था कि आप प्रदर्शन की तिथि बदल लीजिए। छह सितंबर की तिथि में खास क्या है। अगर पुलिस उस तारीख पर सहमत नहीं है तो आप दूसरी तारीख तय कर लीजिए। उच्च न्यायालय ने कहा था कि अगर आप तारीख बदलते हैं तो वो दिल्ली पुलिस को सुने बिना प्रदर्शन की अनुमति देगी। तब करणी सेना की ओर से पेश वकील ने कहा था कि वो इसके पहले भी एक बार तारीख

बदल चुके हैं और ये उनकी दूसरी तारीख है। करणी सेना ने कहा कि उनकी ये पदयात्रा है जो जंतर-मंतर पर समाप्त होगी। तब कोर्ट ने कहा था कि वो दिल्ली पुलिस का पक्ष जानने के बाद ही इस पर विचार करेगी। याचिका करणी सेना के प्रमुख राज शेखावत ने दायर की थी। करणी सेना ने यूजीसी के नियमों के खिलाफ प्रदर्शन करने की अनुमति मांगी थी। इसके लिए दिल्ली पुलिस को 27 अगस्त को पत्र लिखकर कहा गया था कि वे शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। 28 अगस्त को दिल्ली पुलिस ने उनकी अर्जी ये कहते हुए नामंजूर कर दी थी कि ब्रिक्स सम्मेलन की तैयारी चल रही है। करणी सेना ने दिल्ली पुलिस के इसी आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।

## गुरुग्राम में अलॉय व्हील का ट्रायल लेने के बहाने कार समेत युवक फरार

**गुरुग्राम।** सेक्टर 12ए स्थित ऑटोमोबाइल मार्केट स्थित सिद्धदाता टायर्स नामक दुकान से एक युवक अलॉय व्हील डलवाकर ट्रायल के बहाने कार लेकर फरार हो गया। आरोपी सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद उसके परिजनों ने दुकानदार को एक लाख 20 हजार चुकाकर समझौता कर लिया। दुकान मालिक दीपक चौधरी के अनुसार 30 अगस्त को एक युवक काली हुंडई वरना में अलॉय व्हील डलवाने आया। कर्मचारियों ने उसकी पसंद के अलॉय फिट कर दिए। युवक ने परफॉर्मेंस चेक करने के लिए ट्रायल की बात कही तो सुरक्षा के लिहाज से एक कर्मचारी को साथ भेजा गया। कुछ दूर जाकर आरोपी ने कर्मचारी को धमकाया और मारपीट कर बीच रास्ते में गाड़ी से उतार दिया और तेज रफ्तार में कार लेकर फरार हो गया। कर्मचारी ने वापस आकर मालिक को जानकारी दी। मालिक ने सेक्टर-14 थाने में शिकायत दी और सीसीटीवी फुटेज के साथ वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर पहचान बताने वाले को पांच हजार रुपये इनाम की घोषणा की।

## खुले में घूमने वाले पशुओं को पकड़ने का एजेंसी को ठेका, काम शुरू

**गुरुग्राम।** नगर निगम गुरुग्राम की ओर से शहर के विभिन्न जोन को क्लस्टर में बांटकर पशुओं को पकडऩे एवं सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने के लिए एसआर एंटरप्राइजेज एजेंसी को कार्य सौंपा गया हैं। एजेंसी को दो वर्ष तक की आयु वाले बछड़ों तथा दो वर्ष से अधिक आयु वाले गाय एवं बैलों को पकडऩे और निर्धारित स्थान तक ले जाने का कार्य सौंपा गया है। नगर निगम ने एजेंसी को निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अनुसार कार्य करने, आवश्यक वाहनों की तैनाती करने और कार्य का लॉग बुक में रिकॉर्ड रखने के निर्देश दिए हैं। नगर निगम ने डेयरी संचालकों एवं पशुपालकों को हिदायत दी है कि वे अपने पशुओं को अपने परिसर में ही सुरक्षित रूप से बांधकर रखें और उन्हें सडक़ों, गलियों या सार्वजनिक स्थानों पर खुला न छोड़ें। सडक़ों पर खुले घूमने वाले पशुओं के कारण वाहन चालकों के लिए दुर्घटना का खतरा बना रहता है। विशेष रूप से रात के समय और व्यस्त सडक़ों पर अचानक सामने आने वाले पशुओं से गंभीर हादसे हो सकते हैं।

नगर निगम द्वारा खुले में घूमने वाले पशुओं को पकडऩे की कार्रवाई के दौरान यदि कोई पशु डेयरी या पशुपालक का है, तो उस पशु को पकडक़र गौशाला में भेज दिया जाएगा। नगर निगम की पशु पकडऩे वाली टीमों द्वारा कार्रवाई के दौरान एक अन्य गंभीर समस्या भी सामने आती है। कई बार बाइकर ग्रुप/युवक कार्रवाई के दौरान टीमों के आसपास पहुंचकर उन्हें परेशान करते हैं या पशुओं को भगाने का प्रयास करते हैं। इससे कैप्चरिंग अभियान प्रभावित होने के साथ-साथ सडक़ पर अचानक दौड़ते पशुओं के कारण दुर्घटना का खतरा भी बढ़ जाता है। नगर निगम ने ऐसे लोगों को भी चेतावनी दी है कि पशु पकडऩे वाली टीम के सरकारी कार्य में हस्तक्षेप न करें और पशुओं को न भगाएं। पशु को भगाने के दौरान वह अचानक सडक़ पर आ सकता है, जिससे दोपहिया और चारपहिया वाहनों की टक्कर की आशंका रहती है तथा पशु और आम नागरिक दोनों की जान जोखिम में पड़ सकती है।

# फरीदाबादः डिजिटल अरेस्ट के नाम पर करोड़ों की ठगी के दो आरोपी गिरफ्तार

**फरीदाबाद।** फरीदाबाद में डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर एक परिवार से दो करोड़ 13 लाख रूपए ठगने के मामले में साइबर थाना बल्लभगढ़ पुलिस ने ड्राइवर और अकाउंटेंट को पंजाब के जीरकपुर से गिरफ्तार किया है। आरोपियों गौतम (27) और मोहित (25), दोनों लुधियाना, पंजाब के निवासी हैं। पुलिस के अनुसार, गौतम के खाते में ठगी के 65 हजार रुपए आए थे। उसने अपना बैंक खाता मोहित को दिया था और मोहित ने यह खाता आगे साइबर ठगों को उपलब्ध कराया। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि गौतम 11वीं पास है और ड्राइविंग का काम करता है।

वहीं मोहित बीकॉम पास है और एक निजी कंपनी में अकाउंटेंट के पद पर काम करता है। दोनों को सोमवार कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने गौतम को जेल भेज दिया, जबकि मोहित को पांच दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक, 13 जनवरी 2026 को पीड़ित कारोबारी राकेश की पत्नी के मोबाइल पर फोन आया। कॉल करने वाले ने खुद को टेलीकॉम विभाग का अधिकारी बताया और कहा कि उनके आधार कार्ड से जुड़े बैंक खाते में 20 लाख रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। इसके बाद कॉल कथित मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारियों से जोड़ दी गई। ठगों ने पति-पत्नी को लगातार वीडियो कॉल पर रखा और घर से बाहर नहीं निकलने दिया। हर दो घंटे में उनकी गतिविधियों पर नजर रखी। आरोपियों ने खुद को अलग-अलग सरकारी एजेंसियों का अधिकारी बताकर गिरफ्तारी का डर दिखाया। ठगों ने पीड़ित को ईडी के नाम से फर्जी गिरफ्तारी आदेश और सुप्रीम कोर्ट के नाम से फर्जी पत्र भेजे। इनमें बैंक खातों में जमा रकम को जांच के नाम पर बताए गए खातों में भेजने के निर्देश दिए गए। ठगों ने रकम 48 से 72 घंटे में वापस करने का झांसा भी दिया। गिरफ्तारी के डर से पीड़ित ने जनवरी 2026 में अलग-अलग बैंक खातों में कुल दो करोड़ 13 हजार रुपए ट्रांसफर कर दिए। बाद में रकम वापस मांगने पर ठगों के मोबाइल नंबर बंद मिले। इसके बाद पीड़ित ने साइबर थाना बल्लभगढ़ में शिकायत दर्ज कराई।

# गुरुग्राम जिला की 96 ग्राम पंचायतें टीबी मुक्त घोषित

**गुरुग्राम,एजेंसी।** टीबी मुक्त भारत अभियान को जन आंदोलन का रूप देने और जिले को टीबी मुक्त बनाने के उद्देश्य से सोमवार को लघु सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में जिला टीबी फोरम एवं अंतरविभागीय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सीईओ जिला परिषद सुमित कुमार ने की। इस दौरान जिले में टीबी उन्मूलन अभियान के तहत किए जा रहे कार्यों और प्रगति की समीक्षा की गई। साथ ही उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने टीबी उन्मूलन की शपथ लेकर जिले को टीबी मुक्त बनाने में सक्रिय भागीदारी निभाने का संकल्प लिया।

सुमित कुमार ने कहा कि टीबी उन्मूलन केवल स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसमें सभी विभागों, जनप्रतिनिधियों, पंचायतों, सामाजिक संस्थाओं और आमजन की सामूहिक भागीदारी आवश्यक है। बैठक में बताया गया कि जनवरी से अगस्त 2026 तक गुरुग्राम में कुल 9,634 टीबी मरीजों की अधिसूचना दर्ज की गई, जो निर्धारित 8,000 के लक्ष्य का 120 प्रतिशत है। सरकारी क्षेत्र में 2,723 मरीजों की अधिसूचना हुई, जबकि निजी क्षेत्र में 6,911 मरीजों की अधिसूचना दर्ज की गई। बैठक में टीबी मरीजों को गोद लेने की

दिशा में भी प्रगति की समीक्षा की गई। जिले में 6,480 मरीजों में से 3,626 मरीजों ने गोद लेने के लिए सहमति दी, जो 56 प्रतिशत है। इनमें से 958 मरीजों को गोद लिया जा चुका है, जो 26 प्रतिशत है। वहीं उपचार के मामले में जिले की सफलता दर 87 प्रतिशत दर्ज की गई। जिले में 96 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया है।

इनमें 71 ग्राम पंचायतों को कांस्य, 24 को रजत तथा एक ग्राम पंचायत को स्वर्ण श्रेणी प्राप्त हुई है। सीईओ सुमित कुमार ने कहा कि ग्राम पंचायतों की सक्रिय भागीदारी से ग्रामीण क्षेत्रों में टीबी के प्रति जागरूकता बढ़ाने और संभावित मरीजों की पहचान करने में मदद मिलेगी। सीईओ जिला परिषद ने कहा कि टीबी के लक्षणों को छिपाने के बजाय समय पर जांच करवानी चाहिए। शुरुआती पहचान और पूरा उपचार मरीज को स्वस्थ करने के साथ-साथ संक्रमण की श्रृंखला को तोडऩे में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

# बंगाल में भारतीय शिक्षा-दृष्टि को बल देने की अनुकरणीय घोषणा

**ललित गर्ग**

पश्चिम बंगाल में शिक्षा के क्षेत्र में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की ओर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख शैक्षणिक प्रकल्प विद्या भारती के कम से कम एक हजार नए विद्यालय स्थापित करने का लक्ष्य केवल विद्यालयों की संख्या बढ़ाने की घोषणा नहीं है, बल्कि इसे राज्य की शिक्षा-दृष्टि में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के संकेत के रूप में देखा जाना चाहिए। 4 सितंबर 2026 को सामने आई इस घोषणा के अनुसार अगले एक वर्ष में राज्य के प्रत्येक जिले, नगरपालिका और पंचायत तक विद्या भारती के विद्यालयों का विस्तार करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में पश्चिम बंगाल में विद्या भारती से जुड़े 313 विद्यालय संचालित होने की बात कही गई है। मुख्यमंत्री ने विद्या भारती के नेतृत्व को राज्य सचिवालय में शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर इस योजना को आगे बढ़ाने का भी निमंत्रण दिया है। यह घोषणा इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि विद्या भारती आज देश के सबसे बड़े स्वैच्छिक शिक्षा-उपक्रमों में से एक है। विद्या भारती के अपने उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार उसका नेटवर्क देशभर में 12,500 से अधिक विद्यालयों तक फैला हुआ है और इनमें 35 लाख से अधिक विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। उसके विद्यालय पूर्व-प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्तर तक शिक्षा प्रदान करते हैं तथा खेल, संगीत, कला, विज्ञान, संस्कार और सामाजिक उत्तरदायित्व जैसे क्षेत्रों को भी शिक्षा का हिस्सा मानते हैं। हाल के समाचारों में देशभर में 12,000 से अधिक विद्यालयों और लगभग 10,000 बाल संस्कार केंद्रों का उल्लेख भी हुआ है। आंकड़ों में अंतर अलग-अलग वर्षों और संस्थागत गणना-पद्धतियों के कारण हो सकता है, लेकिन इससे विद्या भारती के व्यापक शैक्षिक विस्तार की तस्वीर स्पष्ट होती है।

विद्या भारती की विशेषता केवल यह नहीं है कि वह विद्यालयों की एक बड़ी शृंखला संचालित करती है। उसकी मूल अवधारणा शिक्षा को ज्ञान, संस्कार, चरित्र, राष्ट्रबोध और सामाजिक उत्तरदायित्व से जोड़ने की है। संस्था स्वयं अपने उद्देश्य में भारतीय मूल्यों और संस्कृति पर आधारित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, राष्ट्रभावना, आत्मनिर्भरता और सामाजिक जिम्मेदारी को प्रमुखता देती है। ग्रामीण, जनजातीय, सीमावर्ती और अपेक्षाकृत वंचित क्षेत्रों में शिक्षा का विस्तार भी उसके घोषित उद्देश्यों का हिस्सा है। यहीं से पश्चिम बंगाल की नई पहल का व्यापक महत्व सामने आता है। बंगाल भारत की सांस्कृतिक चेतना का एक अत्यंत समृद्ध केंद्र रहा है। रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, रवींद्रनाथ ठाकुर, बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय और अनेक महापुरुषों ने भारतीय चिंतन, शिक्षा, साहित्य और राष्ट्रचेतना को नई दिशा दी। इसलिए बंगाल की शिक्षा व्यवस्था में भारतीय ज्ञान, संस्कृति, मातृभाषा, स्थानीय इतिहास और राष्ट्रीय दायित्व को उचित स्थान देना किसी राजनीतिक आग्रह से अधिक व्यापक सांस्कृतिक आवश्यकता के रूप में देखा जा सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी इसी दिशा में कई महत्वपूर्ण प्रावधान करती है। नीति का उद्देश्य विद्यार्थी में भारतीय होने के प्रति गहरी आत्मगौरव भावना विकसित करने के साथ ज्ञान, कौशल, मूल्यों और जिम्मेदार नागरिकता का विकास करना है। विशेष रूप से उल्लेखनीय यह है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय ज्ञान परंपरा को शिक्षा से जोड़ने की बात करती है। इसमें भारतीय ज्ञान प्रणालियों, जनजातीय ज्ञान, पारंपरिक सीखने की पद्धतियों, योग, दर्शन, साहित्य, कृषि, वास्तुकला, चिकित्सा, खेल और अन्य भारतीय योगदानों को वैज्ञानिक एवं प्रमाणिक ढंग से पाठ्यक्रम में स्थान देने की बात कही गई है। नीति यह भी कहती है कि पाठ्यचर्या भारतीय और स्थानीय संदर्भ, संस्कृति, परंपरा, भाषा, भूगोल तथा ज्ञान-परंपराओं से जुड़ी होनी चाहिए। इस दृष्टि से देखें तो विद्या भारती का शैक्षिक प्रयोग और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनेक लक्ष्य एक-दूसरे के पूरक दिखाई देते हैं। अंतर यह है कि नीति एक राष्ट्रीय नीति-ढांचा उपलब्ध कराती है, जबकि विद्या भारती जैसा सामाजिक संगठन लंबे समय से विद्यालय स्तर पर मूल्याधारित शिक्षा का अपना प्रयोग करता आया है। इसलिए यदि पश्चिम बंगाल सरकार इस विस्तार को गुणवत्तापूर्ण शिक्षक प्रशिक्षण, आधुनिक विज्ञान, तकनीक, डिजिटल शिक्षा, कौशल विकास और संवैधानिक मूल्यों के साथ जोड़ती है तो इसका प्रभाव केवल नए विद्यालय खोलने तक सीमित नहीं रहेगा।

विद्यालय खोलना अपेक्षाकृत आसान है, लेकिन अच्छे शिक्षक, प्रशिक्षित प्रधानाचार्य, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं, खेल सुविधाएं, डिजिटल संसाधन और गुणवत्तापूर्ण पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराना कहीं अधिक कठिन कार्य है। इसलिए इस पहल की सफलता संख्या से नहीं, शिक्षा की गुणवत्ता से मापी जानी चाहिए। यदि नए विद्यालय केवल भवन बनकर रह गए तो लक्ष्य अधूरा होगा; यदि वे अच्छे शिक्षक और अच्छे नागरिक बनाने के

केंद्र बनते हैं, तभी यह पहल ऐतिहासिक सिद्ध होगी। यहीं स्वयंसेवी संगठनों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। देश के अनेक सरकारी विद्यालय संसाधनों की कमी, शिक्षक-अभाव, आधारभूत सुविधाओं की कमजोरी, तकनीकी पिछड़ेपन और स्थानीय सहभागिता की कमी जैसी समस्याओं से जूझते रहे हैं। सरकार अकेले प्रत्येक विद्यालय की हर आवश्यकता पूरी करे, यह व्यावहारिक रूप से कठिन है। ऐसे में सामाजिक और स्वयंसेवी संस्थाओं को सरकार के प्रतिस्पर्धी नहीं, बल्कि सहयोगी के रूप में देखा जाना चाहिए। विद्या भारती के विस्तार के साथ यह सहयोग एक नया मॉडल विकसित कर सकता है-सरकार आधारभूत संरचना और नियामक सहयोग दे, स्वयंसेवी संगठन शैक्षिक नवाचार, शिक्षक प्रशिक्षण, सामुदायिक भागीदारी और मूल्याधारित कार्यक्रमों में योगदान करें तथा स्थानीय समाज विद्यालय को अपना संस्थान समझकर उसके विकास में सहभागी बने। विद्या भारती के विस्तार के साथ यदि व्यापक शिक्षक प्रशिक्षण अभियान चलाया जाए, जिसमें भारतीय दर्शन के साथ आधुनिक शिक्षाशास्त्र, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल तकनीक, मनोविज्ञान, कौशल शिक्षा और नई मूल्यांकन पद्धतियां शामिल हों, तो यह पूरे देश के लिए अनुकरणीय मॉडल बन सकता है।

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मुर्शिदाबाद और दक्षिण 24 परगना जैसे क्षेत्रों में विशेष विस्तार की बात भी कही है और वहां राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों को लेकर चिंता व्यक्त की है। इन राजनीतिक आरोपों से अलग शिक्षा की दृष्टि से मूल प्रश्न यह है कि संवेदनशील और सामाजिक रूप से विविध क्षेत्रों में विद्यालय नागरिकता-बोध, संवैधानिक कर्तव्य, सामाजिक समरसता, वैज्ञानिक सोच और राष्ट्रीय एकता को कितना मजबूत कर सकते हैं। शिक्षा का सर्वोत्तम उत्तर किसी समुदाय के विरुद्ध अविश्वास पैदा करना नहीं, बल्कि हर बच्चे में जिम्मेदार और जागरूक भारतीय नागरिकता का निर्माण करना है। वंदे मातरम्, भारतीय संस्कृति और राष्ट्रभावना जैसे विषयों को लेकर मुख्यमंत्री के वक्तव्य ने बहस को राजनीतिक आयाम जरूर दिया है। लेकिन दीर्घकालीन दृष्टि से आवश्यकता ऐसी शिक्षा की है जिसमें राष्ट्रप्रेम स्वाभाविक संस्कार बने, आदेश या भय का विषय नहीं। पश्चिम बंगाल की यह पहल इसलिए संपूर्ण राष्ट्र के लिए भी एक महत्वपूर्ण सबक या प्रेरणा है कि शिक्षा केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं हो सकती। सरकार, समाज, अभिभावक, शिक्षक, उद्योग, स्वयंसेवी संस्थाएं और पूर्व विद्यार्थी-सभी मिलकर शिक्षा का नया सामाजिक तंत्र बना सकते हैं। यदि विद्या भारती के पास संगठनात्मक अनुभव है, सरकार के पास संसाधन और नीतिगत शक्ति है तथा समाज के पास सहभागिता की क्षमता है, तो इन तीनों का समन्वय शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। आज भारत को ऐसी शिक्षा चाहिए जो आधुनिक भी हो और अपनी जड़ों से जुड़ी हुई भी; वैज्ञानिक भी हो और संस्कारवान भी; रोजगारपरक भी हो और चरित्रनिर्माणकारी भी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने इसके लिए नीतिगत दिशा दी है। अब आवश्यकता है कि विभिन्न राज्य और सामाजिक संगठन अपने-अपने स्तर पर इसके प्रभावी प्रयोग प्रस्तुत करें। पश्चिम बंगाल में विद्या भारती के एक हजार नए विद्यालयों का लक्ष्य इसी संदर्भ में एक प्रयोगशाला बन सकता है। शुभेंदु अधिकारी की घोषणा इसलिए बधाई के योग्य है कि इसने शिक्षा को राजनीतिक विमर्श से आगे बढ़ाकर सामाजिक सहभागिता और भारतीय शिक्षा-दृष्टि के विमर्श के केंद्र में ला दिया है। अब असली परीक्षा घोषणा की नहीं, उसके क्रियान्वयन की है। यदि एक वर्ष में विद्यालयों की संख्या बढ़ाने के साथ शिक्षक की गुणवत्ता, पाठ्यक्रम की प्रासंगिकता, आधुनिक विज्ञान, तकनीकी दक्षता, भारतीय ज्ञान परंपरा, नैतिकता, संवैधानिक चेतना और सामाजिक समरसता को समान महत्व दिया गया, तो बंगाल का यह प्रयोग केवल बंगाल का नहीं रहेगा। यह भारत को यह संदेश दे सकता है कि शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए केवल नई इमारतें नहीं, नई दृष्टि और समाज की सक्रिय सहभागिता भी आवश्यक है। और शायद यही आज के भारत की सबसे बड़ी शैक्षिक आवश्यकता है-'ज्ञान आधुनिक हो, दृष्टि वैज्ञानिक हो, चरित्र भारतीय हो और शिक्षा का अंतिम लक्ष्य राष्ट्र एवं मानवता का कल्याण हो।

समाज के समग्र विकास के लिए हर तरह के ज्ञान व कुशलताओं की ही नहीं, हर तरह की चीज़ों व हर तरह के लोगों की भी आवश्यकता होती है। बड़ी-बड़ी मशीनें जितनी महत्वपूर्ण होती हैं, उतनी ही महत्वपूर्ण होती हैं सामान्य उपयोग की छोटी-मोटी वस्तुएं भी। यदि फिर भी हमें लगता है कि हम सचमुच बहुत अच्छा नहीं कर पाए हैं तो ये पता चलना भी हमारे पूर्व में संचित ज्ञान और अनुभवों का ही परिणाम है, जो अपने आप में एक उपलब्धि ही है। यह हमें हमारे जीवन के शेषांश के लिए सही स्थितियों का चुनाव करने में सहायक होगा। वैसे भी ज्ञान-विज्ञान अथवा सीखने की कोई सीमा नहीं। ज्ञान-विज्ञान के मुकाबले में मनुष्य के सीखने का काल अथवा उसकी जीवनावधि अत्यंत अल्प है। अपने पूरे एक जीवन में इस ब्रह्मांड के अथाह समुद्र रूपी ज्ञान की एक बूंद मात्र भी हम पूरी तरह से नहीं सीख सकते। संपूर्ण ज्ञान की बात करना ही निरर्थक होगा। यहां आकर हम द्वंद्व में फंस जाते हैं कि हम क्या सीखें और क्या न सीखें? क्या हम यूं ही जीवन को गुज़ार दें? नहीं। जीवन को हमें एक अच्छे तरीके से जीने का भरसक प्रयास करना चाहिए। जीवन को चलाने के लिए कुछ व्यावहारिक व कुछ विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। जीवन में कहीं विशेष सिद्धांतों का पालन करना अनिवार्य होता है तो कहीं व्यावहारिक पक्ष को देखना। एक प्रतिष्ठित विद्वान प्रोफेसर व एक अनपढ़ नाविक की कथा तो आपने सुनी ही होगी। एक बार एक प्रोफेसर समुद्री जहाज़ से यात्रा कर रहे थे। वहां उनकी दोस्ती एक नाविक से हो गई। एक दिन विद्वान प्रोफेसर ने नाविक से पूछा, 'क्या तुमने दर्शन शास्त्र पढ़ा है?' नाविक ने नकारात्मक मुद्रा में सिर हिलाते हुए कहा, 'नहीं।' इस पर प्रोफेसर ने नाविक से कहा कि दर्शन शास्त्र न पढ़कर उसने अपनी ज़िंदगी का चौथाई भाग व्यर्थ कर डाला है। अगले दिन विद्वान प्रोफेसर ने नाविक से फिर पूछा, 'क्या तुमने साहित्य का अध्ययन किया है?' इस बार फिर नाविक ने नकारात्मक मुद्रा में सिर हिलाते हुए कहा, 'नहीं, मुझे तो पता ही

# वर्तमान को जीना भी है एक कला

**सीताराम गुप्ता**

कुछ लोग अपने जीवन में इस बात को लेकर बड़े निराश होते रहते हैं कि वे बहुत-सी चीज़ों, बातों अथवा जानकारी से वंचित रह गए। उनका मानना होता है कि वे अपने जीवन को और अधिक अच्छा बना सकते थे। अधिक पुस्तकें पढ़ सकते थे अथवा सत्संग आदि में अधिक समय व्यतीत कर सकते थे। अधिक योग्य, ज्ञानवान अथवा धार्मिक हो सकते थे। अधिक लोगों से मेलजोल बढ़ाकर अपना सामाजिक दायरा अधिक विस्तृत कर सकते थे। तात्पर्य यही है कि समय का और अधिक अच्छा उपयोग कर सकते थे। यदि हम जीवन में बहुत-सी चीज़ों, बातों अथवा जानकारी से वंचित भी रह गए तो भी हमें मायूस होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वास्तविकता यही है कि हमारी सीमाएं अवश्य होती हैं। वास्तव में जो नहीं किया या नहीं हो सका, उस पर ध्यान देने के बजाय हमें अपना सारा ध्यान इस बात पर केंद्रित करना चाहिए कि हमें आगे क्या करना है और कैसे करना है? आज तक हमने जो भी किया है, अपनी क्षमता और योग्यता के अनुसार अच्छा ही किया है, इस बात को मन में रखें और आज तक जो भी प्राप्त किया है, उसका पूरा-पूरा उपयोग अपने और समाज के हित में करें। यदि हम अपने अल्प ज्ञान अथवा कुशलताओं के बल पर एक बेहतर संतुलित जीवन व्यतीत कर रहे हैं और हमारे कारण समाज का अहित नहीं, कुछ न कुछ हित ही हो रहा है तो ये भी बहुत बड़ी बात है। समाज के समग्र विकास के लिए हर तरह के ज्ञान व कुशलताओं की ही नहीं, हर तरह की चीज़ों व हर तरह के लोगों की भी आवश्यकता होती है। बड़ी-बड़ी मशीनें जितनी महत्वपूर्ण होती हैं, उतनी ही महत्वपूर्ण होती हैं सामान्य उपयोग की छोटी-मोटी वस्तुएं भी। यदि फिर भी हमें लगता है कि हम सचमुच बहुत अच्छा नहीं कर पाए हैं तो ये पता चलना भी हमारे पूर्व में संचित ज्ञान और अनुभवों का ही परिणाम है, जो अपने आप में एक उपलब्धि ही है। यह हमें हमारे जीवन के शेषांश के लिए सही स्थितियों का चुनाव करने में सहायक होगा।

वैसे भी ज्ञान-विज्ञान अथवा सीखने की कोई सीमा नहीं। ज्ञान-विज्ञान के मुकाबले में मनुष्य के सीखने का काल अथवा उसकी जीवनावधि अत्यंत अल्प है। अपने पूरे एक जीवन में इस ब्रह्मांड के अथाह समुद्र रूपी ज्ञान की एक बूंद मात्र भी हम पूरी तरह से नहीं सीख सकते। संपूर्ण ज्ञान की बात करना ही निरर्थक होगा। यहां आकर हम द्वंद्व में फंस जाते हैं कि हम क्या सीखें और क्या न सीखें? क्या हम यूं ही जीवन को गुज़ार दें? नहीं। जीवन को हमें एक अच्छे तरीके से जीने का भरसक प्रयास करना चाहिए। जीवन को चलाने के लिए कुछ व्यावहारिक व कुछ विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। जीवन में कहीं विशेष सिद्धांतों का पालन करना अनिवार्य होता है तो कहीं व्यावहारिक पक्ष को देखना। एक प्रतिष्ठित विद्वान प्रोफेसर व एक अनपढ़ नाविक की कथा तो आपने सुनी ही होगी। एक बार एक प्रोफेसर समुद्री जहाज़ से यात्रा कर रहे थे। वहां उनकी दोस्ती एक नाविक से हो गई। एक दिन विद्वान प्रोफेसर ने नाविक से पूछा, 'क्या तुमने दर्शन शास्त्र पढ़ा है?' नाविक ने नकारात्मक मुद्रा में सिर हिलाते हुए कहा, 'नहीं।' इस पर प्रोफेसर ने नाविक से कहा कि दर्शन शास्त्र न पढ़कर उसने अपनी ज़िंदगी का चौथाई भाग व्यर्थ कर डाला है। अगले दिन विद्वान प्रोफेसर ने नाविक से फिर पूछा, 'क्या तुमने साहित्य का अध्ययन किया है?' इस बार फिर नाविक ने नकारात्मक मुद्रा में सिर हिलाते हुए कहा, 'नहीं, मुझे तो पता ही

नहीं साहित्य क्या होता है।' इस पर प्रोफेसर ने नाविक से कहा, 'यदि तुमने साहित्य का अध्ययन नहीं किया है तो तुमने अपनी ज़िंदगी का आधा भाग व्यर्थ कर डाला है।

प्रोफेसर और नाविक के मध्य वार्तालाप चल ही रहा था कि तभी समुद्र में तूफ़ान आ गया और ऊंची-ऊंची लहरें उठने लगीं। जहाज़ बुरी तरह से हिलने लगा। तूफ़ान के शोर में एक-दूसरे की आवाज़ तक नहीं सुनाई पड़ रही थी। तभी नाविक ने चिल्लाकर प्रोफेसर से पूछा, 'प्रोफेसर साहब, क्या आपको तैरना आता है?' प्रोफेसर ने कहा कि उसे तैरना नहीं आता। इस पर नाविक ने कहा, 'प्रोफेसर साहब, आपने तो अपनी पूरी ज़िंदगी ही व्यर्थ कर डाली है। अभी जहाज़ डूबने वाला है और जिसे तैरना आता है, उसी के बच निकलने की संभावना है।' यह कहकर नाविक अपनी जान बचाने के लिए समुद्र में कूद गया। संदेश स्पष्ट है। जीवन में जितना महत्व विशिष्ट ज्ञान का है, उससे अधिक महत्व सामान्य व्यावहारिक ज्ञान व कुशलताओं का भी है। हम जीवन में सहजता-सरलता की उपेक्षा कर ही नहीं सकते। डिज़रायली का एक कथन है कि हमें दुनिया की सारी चीज़ों के बारे में कुछ-कुछ और कुछ एक के बारे में सब कुछ सीखने की कोशिश करनी चाहिए। हम दुनिया की तमाम चीज़ों के बारे में सब कुछ नहीं सीख सकते। लेकिन कुछ भी न सीखना भी ठीक नहीं। जब हमें इस संसार में रहना है तो इस संसार की व्यावहारिकता को भी जानना ही चाहिए, अन्यथा जीवन संकट में पड़ जाएगा। हम चौबीसों घंटे पूरी दुनिया का नक्शा अपने दिमाग में न रखें, लेकिन जिस रास्ते से भी गुज़रें, विशेष रूप से उसका नक्शा ज़रूर अपने दिमाग में रखें। जीवन-यात्रा में जहां भी खूबसूरत फूल खिले मिलें, उनसे अवश्य आनंदित हों। फिर हमारे जीवन के अगले क्षण की ही क्या गारंटी है? कल भी हमारी आंखों के सामने सुंदर-सुंदर फूल खिले हों, इसके लिए नए बीज बोते रहें, लेकिन वर्तमान की उपेक्षा किसी भी तरह से उचित नहीं।

## विचार

# सत्य निकेतन हादसा: किराये के मकान में जीवन की कीमत कम

**डॉ.रमेश ठाकुर**

मानवीय हिमाकत के चलते दिल्ली में और एक दर्दनाक घटना घट गई। सत्य निकेतन के मोतीनगर स्थिति एक सालों पुरानी जर्जर हालत की बिल्डिंग मौत बनकर रिमझिम बारिश में भरभराकर गिर पड़ी। घटना की सूचना पाकर पहुंचे बच्चों के परिजनों की चीखें कलेजा फाड़ रही हैं। परिजन बिलख रहे हैं। मां बदहवास और बेसुध हैं। स्थानीय पुलिस और हुकूमती अधिकारियों का घटनास्थल पर जमघट लगा है। राहत-बचाव कार्य जारी है। घायल बच्चे एम्स के ट्रामा सेंटर भिजवाए जा रहे हैं। लेकिन वहां से कुछ बच्चों के न रहने की सूचनाए हर किसी को झकझोर रही है। बिल्डिंग में रहने वाले बच्चे तकरीबन बाहरी प्रदेशों के थे। वह अपना उज्ज्वल भविष्य बनाने की चाह लेकर शिक्षा प्राप्त करने पहुंचे थे। पर, उन्हें क्या पता हादसों का रूप ले चुकी दिल्ली उनकी जान ले लेगी। पढ़ने वाले बच्चों के साथ दिल्ली में आए दिन कोई न कोई हादसा होता ही रहता है। राजेंद्र नगर स्थिति कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से हुई बच्चों की मौत को शायद ही कोई भूल पाया हो। मुखर्जी नगर के कोचिंग सेंटर में आग लगने की घटना की याद आते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस तरह के हर हादसे पर जिम्मेदार अधिकारियों और नेताओं का हमेशा से एक ही बयान होता है। दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, सख्त कार्रवाई होगी। इसके अलावा मृतकों के परिजनों को मुआवजा और घायलों की इलाज कराकर मामला रफा-दफा कर दिया जाता है। जब तक मीडिया में घटना की चर्चा होती है, कार्रवाई के नाम पर सरकारी डंडा पीटा जाता है। शोर जैसे ही शांत होगा, जांच-पड़ताल ठंडे बस्ते में चली जाएगी। जमींदोज हुई इस बिल्डिंग में ज्यादातर युवा विश्व विद्यालय में पढ़ते थे या सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे। मालिक ने बिल्डिंग को करीब 30 सालों से पीजी के लिए किसी अन्य को किराये पर दिया हुआ था। बिल्डिंग मानकों के एकदम विरुद्ध निर्मित हुई थी। क्षेत्रफल मात्र 55 गज का था, जिसमें 30 कमरे बना रखे थे। बिल्डिंग 40 से 45 साल पुरानी बताई जाती है। मालिक पर मुकदमा हुआ है। एकाध महीने बाद उसे जमानत मिल जाएगी। उसी जगह पर फिर से दूसरी बिल्डिंग तान दी जाएगी।

दिल्ली विश्वविद्यालय क्षेत्र में बने पीजी को लेकर 'इंडियन जियोटेक्निकल कॉन्फ्रेस' ने कुछ वर्ष पहले एक रिसर्च किया था जिसमें पाया गया कि 85 फीसदी पीजी रहने के लायक नहीं हैं। इस तरह की रिसर्च रिपोर्ट को भी हुकूमत ने दरकिनार किया। हादसे का शिकार हुई बिल्डिंग के निर्माण में घोर मानवीय हिमाकत का तांडव किया गया। आरोप है कि दिल्ली नगर निगम से लेकर, पुलिस, फायर ब्रिगेड और सरकार के अधिकारियों ने घूस खायी। घटनास्थल साउथ दिल्ली का सत्य निकेतन क्षेत्र है, जिसे डूब या निचला-धरातल क्षेत्र भी कहते हैं। वहां बिल्डिंग बनाने की मात्र ढाई मंजिला इजाजत होती है। पर, अधिकारियों ने घूस खाकर पांच मंजिला तक बनवा दिया। दिल दहला देने वाले हादसे को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही है कि बिल्डिंग में अवैध निर्माण होता रहा और जिम्मेदार लोग आंख मूंदकर तमाशबीन बने रहे। इतना ही नहीं, करीब 40 साल पुरानी इस बिल्डिंग में बारिश के दौरान हर साल बेसमेंट जलमग्न हो जाता था, जिससे इसकी नींव कमजोर होती गई और इस साल वजन नहीं सहन कर पाई जिससे भराभरकर ढह गई। हादसे की जिम्मेदारी शायद ही कोई ले? क्योंकि ऐसे हादसे दिल्ली में समय-समय पर होते रहे हैं। कुछ महीनों पहले ही एक अवैध होटल में आग लगने से विदेशी सहित कई लोग जलकर खाक हुए थे। बिल्डिंग्स का गिरना तो दिल्ली में आम हो चुका है। दिल्ली में अवैध कॉलोनियों की भरमार है। कहने को तो अवैध हैं लेकिन अधिकारी घूस लेकर उसे चंद मिनटों में वैध कर देते हैं। दिल्ली में इस समय करीब 1731 अवैध कॉलोनियां और 650 से लेकर 675 झुग्गी झोपड़ियां हैं जिनमें ज्यादातर किराएदार ही रहते हैं। दिल्ली ऐसा शहर है जहां देश के सभी प्रांतों के लोग रोजी रोटी कमाने आते हैं। शिक्षा का हब भी दिल्ली है। जहां सिविल सेवा की तैयारियां करने बच्चे दूर-दराज से पहुंचते हैं। 5 लाख बच्चे सालाना सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी करने दिल्ली के मुखर्जी नगर आते हैं, रहने के लिए उन्हें पीजी चाहिए होता है। ऐसे में बच्चे सस्ता पीजी खोजते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता सस्ता घर उनकी जान ले लेगा? वहीं, करीब 15 लाख बच्चे अन्य प्रदेशों के दिल्ली के विभिन्न कॉलेजों में अध्ययनरत हैं। जहां हादसा हुआ, उस इलाके में तकरीबन घर पीजी में तब्दील हैं। पीजी के नाम पर बड़ा नेक्सस उस इलाके में चलता है जिसका मकान होता है वह खुद पीजी संचालित नहीं करता, बल्कि वह किसी अन्य को ठेके पर दे देता है। ठेकेदार बच्चों को कमरों में भूसे की तरह ठूस देते हैं। जहां न कोई सुविधा, न मानकों का इस्तेमाल, सिर्फ उन्हें कमाने से मतलब होता है। हादसे वाली बिल्डिंग गिरने का संकेत कुछ वर्षों से दे रही थी? लेकिन न मालिक ने गौर किया और न ही अधिकारियों ने, आखिर क्यों? पिछले साल तीसरे माले की सीढ़ियों की छत का ऊपरी हिस्सा गिरा था जिसे रिपेयर करवाकर संभावित हादसे पर पर्दा डाल दिया गया।

## एक नजर

### बिहार के रोहतास में छत पर सोए दो लोगों की गोली मार कर हत्या

**डेहरी आन सोन।** बिहार में रोहतास जिले के सासाराम मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बेदा-बनरसिया गांव में सोमवार अलसुबह लगभग तीन बजे छत पर सोए दो लोगों की अपराधियों ने गोलीमार हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार 40 वर्षीय मणि भूषण कुमार और 40 वर्षीय ननकी देवी की गोलीमार हत्या की गई है। मृतका ननकी देवी बेदा-बनरसिया गांव की रहने वाली थी। मृतका के पुत्र अभिषेक कुमार ने बताया आज सुबह तीन बजे के आसपास छत पर से गोली चलने की आवाज सुनाई देने के बाद मैं कमरे से बाहर निकला, तो कुछ लोग अंधेरे में छत पर से उतरते नजर आए। इसके बाद वे सभी दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ भाग गए। इसके बाद छत पर जाने के बाद देखा की दोनों लोग की मौत हो चुकी है। घटना की सूचना पुलिस को दिए जाने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। मुफस्सिल थानाध्यक्ष राजीव रंजन सिंह नई घटना की पुष्टि की है। फिलहाल पुलिस घटना के कारणों पता लगाने में जुटी हुई है।

### इंजीनियरिंग कॉलेज के मुख्य द्वार पर 2 तो हॉस्टल में 10 फीट तक भरा पानी, ऑनलाइन क्लास शुरू

**भागलपुर,एजेंसी।** गंगा के रिकॉर्ड तोड़ बढ़ते जलस्तर के कारण सिल्क सिटी भागलपुर में बाढ़ की स्थिति लगातार भयावह होती जा रही है। निचली बस्तियों और दियारा इलाकों को जलमग्न करने के बाद बाढ़ का पानी अब शहर के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में भी प्रवेश कर चुका है। इस आपदा का सबसे बड़ा असर भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज पर देखने को मिल रहा है, जिसका पूरा परिसर पूरी तरह जलमग्न हो गया है। कॉलेज के मुख्य द्वार पर करीब 2 फीट तक पानी जमा हो गया है, जबकि छात्र-छात्राओं के छात्रावास में स्थिति और भी ज्यादा गंभीर है। हॉस्टल परिसर में पानी का स्तर 7 से 10 फीट तक पहुंच गया है, जिससे वहां रहना पूरी तरह नामुमकिन हो गया है। स्थिति की गंभीरता और छात्र-छात्राओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कॉलेज प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से छात्रावासों को खाली कराने का आदेश जारी कर दिया है। आदेश के बाद हॉस्टल में रहने वाले छात्र-छात्राएं आनन-फानन में अपना जरूरी सामान, किताबें और बैग समेटकर अपने घरों की ओर लौटने को मजबूर हैं। मामले की गंभीरता पर कॉलेज प्रशासन ने कहा, कैंपस और विशेषकर छात्रावासों में पानी का स्तर बहुत तेजी से बढ़ा है, जिससे वहां रहना छात्रों के लिए असुरक्षित हो गया था। हमारी पहली प्राथमिकता सभी छात्र-छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, इसलिए हॉस्टलों को एहतियातन खाली करा दिया गया है। बाढ़ की स्थिति सामान्य होने तक परिसर को बंद रखा जाएगा। हालांकि, हम छात्रों के शैक्षणिक सत्र को प्रभावित नहीं होने देंगे, जिसके लिए तुरंत वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। बाढ़ के इस बड़े संकट के बीच छात्रों के भविष्य और उनकी पढ़ाई का नुकसान न हो, इसके लिए कॉलेज प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। कॉलेज में ऑफलाइन कक्षाओं को स्थगित कर तत्काल प्रभाव से ऑनलाइन क्लास शुरू कर दी गई हैं। अब सभी छात्र अपने-अपने घरों से ही सुरक्षित रहकर इंटरनेट के माध्यम से अपनी पढ़ाई जारी रख सकेंगे। कॉलेज प्रशासन पूरी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है।

### गंगा के उफान से टीएमबीयू परिसर जलमग्न; हॉस्टल खाली, पठन-पाठन ठप

**भागलपुर।** भागलपुर में गंगा नदी के लगातार बढ़ते जलस्तर ने तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय की मुश्किलें अत्यधिक बढ़ा दी हैं। बाढ़ का पानी अब विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन से लेकर सीनेट हॉल और विभिन्न कॉलेजों के परिसरों तक में फैल चुका है। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि लोग रोजमर्रा के कामकाज के लिए नावों का सहारा लेने को मजबूर हैं। चारों तरफ गंभीर जलजमाव होने के कारण विश्वविद्यालय प्रशासन, कर्मचारियों, छात्र-छात्राओं और अभिभावकों की चिंताएं बढ़ गई हैं। बाढ़ के पानी के कारण विश्वविद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। टीएमबीयू के अंतर्गत आने वाले सिटी कॉलेज और पीएनए साइंस कॉलेज की कक्षाओं को पानी भरने के कारण बंद करना पड़ा है।

मारवाड़ी कॉलेज के हॉस्टल रोड और महिला छात्रावासों में बाढ़ का पानी प्रवेश करने के बाद सुरक्षा के मद्देनजर छात्राओं को तुरंत हॉस्टल खाली करने का निर्देश दिया गया है, जिसके बाद छात्राएं अपने घर लौटने को मजबूर हैं। विश्वविद्यालय पहुंचने वाले छात्र-छात्राओं और अभिभावकों का कहना है कि हर साल बाढ़ के कारण पढ़ाई बाधित होती है। प्रशासन को जल्द से जल्द ऑनलाइन कक्षाओं या अन्य वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार करना चाहिए ताकि जरूरी शैक्षणिक कार्य प्रभावित न हों। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि जलस्तर में अप्रत्याशित बढ़ोतरी को देखते हुए छात्रों और कर्मचारियों की सुरक्षा उनकी पहली प्राथमिकता है। इसी वजह से जलमग्न हो चुके हॉस्टलों को समय रहते खाली कराया गया है। यदि आने वाले दो से तीन दिनों में पानी का स्तर इसी तरह बढ़ता रहा और प्रशासनिक कामकाज पूरी तरह ठप होने की नौबत आई, तो जरूरी आधिकारिक कार्यों को अन्य सुरक्षित स्थानों से संचालित करने और विद्यार्थियों के लिए वैकल्पिक डिजिटल माध्यमों को अपनाने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। प्रशासन जिला प्रशासन के साथ मिलकर स्थिति की लगातार निगरानी कर रहा है। फिलहाल, गंगा के इस रौद्र रूप के सामने विश्वविद्यालय का कामकाज बुरी तरह प्रभावित है और आने वाले दिनों में स्थिति और गंभीर होने की आशंका जताई जा रही है।

# बिहार के बाढ़ प्रभावित वैशाली और सारण जिलों का मुख्यमंत्री ने किया दौरा, उपलब्ध सुविधाओं की ली जानकारी

**पटना,एजेंसी।** बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को बाढ़ प्रभावित वैशाली और सारण जिलों का दौरा किया। उन्होंने हाजीपुर और सोनपुर में संचालित बाढ़ राहत शिविरों का निरीक्षण कर वहां रह रहे बाढ़ पीड़ितों से सीधे संवाद किया और राहत एवं बचाव कार्यों के साथ उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने राहत शिविरों में संचालित सामुदायिक रसोई में भोजन की व्यवस्था का जायजा लिया और स्वयं लोगों को भोजन परोसा। वैशाली जिले में गंगा ब्रिज थाना के सामने संचालित बाढ़ राहत शिविर में मुख्यमंत्री ने कम्युनिटी किचन का निरीक्षण किया। उन्होंने भोजन वितरण काउंटर और निबंधन-सह-नियंत्रण कक्ष की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। भोजन की गुणवत्ता की जांच करने के साथ उन्होंने शिविर में रह रहे लोगों से पूछा कि भोजन, रहने या अन्य सुविधाओं को लेकर उन्हें किसी तरह की परेशानी तो नहीं हो रही है। लोगों ने मुख्यमंत्री को बताया कि शिविर में पर्याप्त भोजन मिल रहा है और व्यवस्थाएं संतोषजनक हैं। मुख्यमंत्री ने राहत शिविर में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र का भी निरीक्षण किया और बच्चों से बातचीत की। उन्होंने शैक्षणिक शिविर में पहुंचकर बच्चों की पढ़ाई, शैक्षणिक गतिविधियों और खान-पान के बारे में जानकारी ली। इसके अलावा महिलाओं और पुरुषों के लिए की गई अलग-अलग आवासीय व्यवस्था का भी जायजा लिया और दोनों शिविरों में रह रहे लोगों से सीधे संवाद किया।

स्वास्थ्य शिविर के निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने चिकित्सकों से उपलब्ध जांच एवं उपचार सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बाढ़ प्रभावित

किसी भी व्यक्ति के बीमार पड़ने पर उसे तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए और इलाज के लिए किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने पशु चिकित्सा शिविर की व्यवस्थाओं की भी जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को पशुओं के लिए पर्याप्त दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पशु चारे की समुचित व्यवस्था करने का निर्देश दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बाढ़ के पानी में डूबने से हुई मौत के मामलों में मृतकों के आश्रितों को चार-चार लाख रुपये की सहायता राशि भी प्रदान की। इसके बाद मुख्यमंत्री सारण जिले के सोनपुर पहुंचे, जहां उन्होंने शहर स्थित स्काउट एंड गाइड सेंटर में संचालित बाढ़ राहत शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने यहां कम्युनिटी किचन की व्यवस्था देखी और शिविर में रह रहे लोगों से बातचीत कर भोजन, आवास और अन्य सुविधाओं की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने बाढ़ पीड़ितों के साथ भोजन भी किया और उसकी गुणवत्ता का जायजा लिया। शिविर में रह रहे लोगों ने राहत एवं व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि शिविर में भोजन, पेयजल और रहने समेत आवश्यक सुविधाओं की अच्छी व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ के कारण हुई फसल क्षति का आकलन कराया जाएगा और प्रभावित किसानों को समुचित मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि गंगा में हर वर्ष आने वाली बाढ़ की समस्या के स्थायी समाधान के लिए भी सरकार प्रयास कर रही है। हाजीपुर और सोनपुर में राहत शिविरों के निरीक्षण के दौरान पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा नदी के जलस्तर में करीब 17 से 18 सेंटीमीटर की गिरावट दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि फरक्का बराज से अभी करीब 15 लाख क्यूसेक पानी का लगातार डिस्चार्ज हो रहा है। अगले दो-तीन दिनों में स्थिति में और सुधार आने की संभावना है।

## लकवा व हृदयाघात से बचाव में फिजियोथेरेपी कारगर : डॉ. विकास

**नवादा।** विश्व फिजियोथेरेपी दिवस के अवसर पर सोमवार को नवादा स्थित आदर्श फिजियोथेरेपी सेंटर में जागरूकता कार्यशाला सह सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन चर्चित फिजियोथेरेपिस्ट डॉ. विकास कुमार ने किया। इस दौरान हृदय रोग, लकवा एवं अन्य शारीरिक समस्याओं से जूझ रहे मरीजों को फिजियोथेरेपी के महत्व और इससे होने वाले लाभों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉ. विकास कुमार ने कहा कि हृदय रोग और लकवा से पीड़ित मरीजों के उपचार एवं पुनर्वास में फिजियोथेरेपी की महत्वपूर्ण भूमिका है। चिकित्सकीय सलाह के अनुसार दवाओं के साथ फिजियोथेरेपी को अपनाने से मरीजों को अपनी शारीरिक क्षमता वापस पाने में काफी मदद मिल सकती है।

उन्होंने कहा कि फिजियोथेरेपी को केवल दर्द कम करने की पद्धति समझना उचित नहीं है, बल्कि यह मरीज के शरीर की कार्यक्षमता, मांसपेशियों की ताकत, संतुलन और दैनिक गतिविधियों को बेहतर बनाने में भी सहायक है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में हृदय रोग तेजी से बढ़ रहा है और बड़ी संख्या में लोगों की मौत हृदयाघात के कारण हो रही है। ऐसे में लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने की जरूरत है। नियमित शारीरिक गतिविधि, संतुलित आहार, तनाव पर नियंत्रण तथा चिकित्सकीय परामर्श के साथ उचित फिजियोथेरेपी हृदय रोगियों के पुनर्वास में उपयोगी साबित हो सकती है। डॉ. विकास ने लकवा से पीड़ित मरीजों के संबंध में कहा कि समय पर उपचार और नियमित फिजियोथेरेपी से मरीज की स्थिति में सुधार लाने में मदद मिल सकती है। लकवा के बाद शरीर के प्रभावित अंगों की गतिविधि को सामान्य करने, मांसपेशियों की जकड़न कम करने तथा मरीज को दोबारा चलने-फिरने और दैनिक कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए नियमित फिजियोथेरेपी जरूरी है। उन्होंने मरीजों और उनके परिजनों से अपील की कि वे चिकित्सकीय सलाह के अनुसार नियमित रूप से फिजियोथेरेपी कराएं और उपचार के दौरान धैर्य बनाए रखें। उन्होंने कहा कि किसी भी बीमारी में दवा और फिजियोथेरेपी का उपयोग विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार ही किया जाना चाहिए। सेमिनार के दौरान मरीजों एवं उनके परिजनों को फिजियोथेरेपी से जुड़ी विभिन्न तकनीकों की जानकारी दी गई। साथ ही हृदय रोग एवं लकवा से बचाव के लिए स्वस्थ जीवनशैली अपनाने पर जोर दिया गया। कार्यक्रम में सेंटर के कर्मियों के अलावा बड़ी संख्या में मरीज एवं उनके परिजन मौजूद रहे।

## बाढ़ पीड़ितों को तत्काल राहत राशि देने और युद्धस्तर पर बचाव कार्य चलाने की मांग, जिलाधिकारी को सौंपा मांग पत्र

**भागलपुर।** गंगा के बढ़ते जलस्तर और बाढ़ की विभीषिका के बीच प्रभावित इलाकों में राहत कार्यों में तेजी लाने की मांग को लेकर बिहार जनसंघर्ष समिति ने सोमवार को भागलपुर जिलाधिकारी को एक मांग पत्र सौंपा। समिति ने प्रशासन से कागजी प्रक्रियाओं को दरकिनार कर युद्धस्तर पर बाढ़ पीड़ितों तक सहायता पहुंचाने की अपील की है। मांग पत्र सौंपने वालों में बिहार जनसंघर्ष समिति के संयोजक गौतम कुमार, सह संयोजक निर्मल कुमार, कोषाध्यक्ष सुभाष कुमार प्रसाद, संरक्षक डॉ. जयंत जलद, उज्ज्वल घोष और दीपक कुमार मंडल मुख्य रूप से शामिल थे।

समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार को संगठन की एक विशेष टीम ने विश्वविद्यालय बाल निकेतन स्कूल, टिल्लाह कोठी, साहेबगंज, लालूचक, श्रीरामपुर, बैरिया, गोसाईदासपुर, मथुरापुर, रशदपुर एवं शंकरपुर सहित विभिन्न बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जमीनी मुआयना किया था। इस दौरान यह बात सामने आई कि गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ने के बावजूद सरकारी राहत एवं बचाव व्यवस्था नाकाफी है। कई प्रभावित इलाकों में लोग जलजमाव, आवागमन, पेयजल, स्वच्छता, बिजली, स्वास्थ्य और खाद्य सामग्री की गंभीर किल्लत से जूझ रहे हैं और अत्यंत दयनीय स्थिति में रहने को मजबूर हैं। इसलिए समिति यह मांग करती है कि राहत राशि देने के लिए बाढ़ समाप्त होने का इंतजार न कराया जाए। संकट की इस घड़ी में सरकारी सहायता का उद्देश्य कागजी प्रक्रिया पूरी करना नहीं, बल्कि समय पर मदद पहुंचाना होना चाहिए। बाढ़ के कारण बंद पड़े विद्यालयों के बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए अस्थायी स्कूल या वैकल्पिक शिक्षण व्यवस्था शुरू की जाए। दियारा और जलमग्न गांवों में लोगों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त सरकारी नावों का इंतजाम हो और पुलिस नियमित रूप से पेट्रोलिंग करे। इंसानों के साथ-साथ पशुओं के लिए भी चारा, भूसा, साफ पानी, सुरक्षित आश्रय स्थल और नियमित पशु चिकित्सा शिविर की व्यवस्था की जाए। गर्भवती महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और गंभीर मरीजों के लिए विशेष स्वास्थ्य शिविर और सुरक्षित निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। समिति ने कहा है कि यदि बाढ़ पीड़ितों तक पारदर्शी और त्वरित तरीके से मदद नहीं पहुंचाई गई, तो वे आंदोलन को और तेज करने के लिए बाध्य होंगे।

## कटिहार बाढ़ संकट: विस्थापित परिवारों को सुरक्षित निकालने के कड़े निर्देश, मुफ्त भोजन-दवा के साथ मिलेगी 7000 की आर्थिक मदद

**कटिहार,एजेंसी।** गंगा, कोशी और सहायक नदियों के बढ़ते जलस्तर के कारण कटिहार जिले में बाढ़ की गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। बड़ी संख्या में प्रभावित परिवार सुरक्षित ऊंचे स्थानों पर शरण ले रहे हैं। हालात से निपटने के लिए जिला पदाधिकारी ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों संग समीक्षा बैठक कर आपदा प्रबंधन की मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के तहत तत्काल राहत कार्य चलाने के निर्देश दिए। बैठक में निर्णय लिया गया कि सभी सुपात्र प्रभावित परिवारों को प्रति परिवार 7,000 रुपये की आनुग्रहित राहत राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी। इसके लिए आपदा सम्पूर्ति पोर्टल पर केवल सत्यापित व जीवित एकल मुखिया के नाम दर्ज करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं, ताकि दोहरी या फर्जी प्रविष्टि न हो सके।

विस्थापितों के लिए चिन्हित स्थलों पर तुरंत सामुदायिक रसोई शुरू करने का आदेश दिया गया है। रसोई में आने वालों का अनिवार्य पंजीकरण किया जाएगा और व्यवस्था की फोटो-वीडियो उच्चाधिकारियों को भेजी जाएगी। शिविरों में पूड़ी और तले हुए खाद्य पदार्थों के वितरण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। सुबह-शाम तय मानक के तहत दाल, चावल और सब्जी का पका हुआ भोजन दिया जाएगा। रसोइयों को श्रम विभाग की निर्धारित दर पर पारिश्रमिक मिलेगा। बाढ़ में फंसे लोगों को निकालना प्रशासन की शीर्ष प्राथमिकता तय की गई है। इसके लिए पर्याप्त नावों की व्यवस्था की जा रही है। केवल निबंधित नावों का परिचालन होगा, जिन पर लाल झंडे के साथ 'सरकारी नाव नि:शुल्क सेवा' लिखा होना अनिवार्य रहेगा। नावों पर ओवरलोडिंग पर सख्त रोक रहेगी और सूर्यास्त के

बाद परिचालन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट करते हुए शिविरों में जीवन रक्षक दवाएं, सर्पदंश रोधी इंजेक्शन, टीके और हैलोजन टैबलेट का भंडारण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। सुदूर क्षेत्रों के लिए बोट एंबुलेंस तैनात रहेगी और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कराया जाएगा। गर्भवती महिलाओं को समय रहते निकालकर अस्पताल में सुरक्षित प्रसव कराने तथा वृद्धों व दिव्यांगों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा शिविरों में टैंकर से पेयजल, अलग-अलग शौचालय, मवेशियों के लिए चारा, क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत और फसल नुकसान के त्वरित आकलन का भी आदेश जारी हुआ। बैठक में अपर समाहर्ता, मनिहारी एसडीएम, सिविल सर्जन, बीडीओ, सीओ और सभी मुखिया उपस्थित रहे।

## भागलपुर में गंगा का रौद्र रूप: आशियाने बहे, अब दाने-दाने को तरस रहे बाढ़ पीड़ित

**भागलपुर,एजेंसी।** जिले में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से बाढ़ की स्थिति अत्यंत विकराल हो चुकी है। नदी के किनारे बसे दियारा इलाकों में बाढ़ का पानी पूरी तरह फैल जाने के बाद, हजारों जिंदगियां तबाही के मुहाने पर खड़ी हैं। अपने ही घर में बेगाने हो चुके लोग भारी मन से अपना आशियाना छोड़कर सुरक्षित और ऊंचे स्थानों की ओर पलायन करने को मजबूर हैं।

नाथनगर प्रखंड के रतीपुर, बैरिया शंकरपुर, अजमेरीपुर, रसीदपुर और श्रीरामपुर समेत कई गांव पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। इन गांवों की गलियां, जहां कभी बच्चों की किलकारियां गूंजती थीं, अब वहां सिर्फ और सिर्फ पानी का सन्नाटा पसरा हुआ है। गांवों में पानी घुसने के बाद बेघर हुए परिवारों ने रविंद्र भवन और टिल्हा कोठी जैसे ऊंचे सरकारी भवनों में शरण ली है। लेकिन राहत की तलाश में पहुंचे इन विस्थापितों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। विस्थापित परिवारों के सामने सिर छुपाने के बाद अब रहने, शुद्ध पीने का पानी, खाने और शौचालय जैसी बुनियादी जरूरतों का भीषण संकट खड़ा हो गया है। कई मजबूर परिवार ऐसे भी हैं जिन्हें भवनों के भीतर जगह नहीं मिली। वे सड़कों के किनारे या खुले मैदानों में तिरपाल तानकर अपना अस्थायी आशियाना बनाने में जुटे हैं। इन अस्थायी तंबुओं में भूख से बिलखते छोटे-छोटे बच्चे और बेबस माता-पिता की तस्वीरें किसी का भी दिल दहलाने के लिए काफी हैं। बाढ़ पीड़ितों की

इस त्रासदी में केवल इंसान ही नहीं, बल्कि बेजुबान पशु भी पिस रहे हैं। ग्रामीण किसी तरह अपनी जान दांव पर लगाकर अपने मवेशियों को सुरक्षित स्थानों पर लेकर तो आए हैं, लेकिन अब उनके सामने पशु चारे का गहरा संकट खड़ा हो गया है। चारागाह पूरी तरह पानी में डूब चुके हैं, जिससे मवेशियों को भूखा रहना पड़ रहा है। लोग अपनों के साथ-साथ इन बेजुबानों की जिंदगी बचाने की दोहरी जद्दोजहद में जुटे हैं। बाढ़ की विभीषिका झेल रहे पीड़ितों का दर्द आंसुओं के रूप में छलक रहा है। एक बाढ़ पीड़ित ने रोते हुए कहा, गंगा मइया ने हमारा सब कुछ छीन लिया। घर डूब गया, अनाज बह गया। अब बच्चों को क्या खिलाएं और खुद कहां जाएं, कुछ समझ नहीं आ रहा। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस भीषण आपदा के बावजूद अब तक उन्हें कोई पर्याप्त सरकारी सहायता नहीं मिली है। राहत सामग्री और कम्युनिटी किचन जैसी सुविधाएं अभी भी प्रभावितों की पहुंच से दूर हैं, जिससे लोगों में भारी आक्रोश है। जैसे-जैसे गंगा का पानी नए इलाकों को अपनी चपेट में ले रहा है, जिला प्रशासन के सामने चुनौतियां पहाड़ जैसी होती जा रही हैं। हजारों की आबादी तक तुरंत सूखा राशन, साफ पानी, चिकित्सा सुविधा और पशु चारा पहुंचाना इस समय सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। देखना यह है कि प्रशासन कागजी दावों से निकलकर जमीनी स्तर पर इन बेबस लोगों के आंसू कब तक पोंछ पाता है।

## बिहार के सीवान में 36 घंटे प्रसव पीड़ा में तड़पती रही एचआईवी रिएक्टिव प्रसूता

**सीवान,एजेंसी।** बिहार में सीवान जिले के मॉडल सदर अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। बसंतपुर प्रखंड के एक गांव की एचआईवी रिएक्टिव प्रसूता करीब 36 घंटे तक प्रसव पीड़ा से तड़पती रही। परिजनों की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वे निजी अस्पताल में जाकर सिजेरियन करा सकें। बावजूद इसके, रविवार की देर शाम महिला वार्ड में तैनात स्वास्थ्यकर्मियों द्वारा कथित तौर पर प्रसूता को परेशान कर अस्पताल से चले जाने के लिए कह दिया गया। आखिरकार बेबस परिजन प्रसूता को लेकर किसी झोलाछाप चिकित्सक के पास चले गये और बाद में अपना मोबाइल बंद कर लिया। मामला तब और गंभीर हो जाता है, जब अस्पताल प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के कई वरीय अधिकारियों को इसकी जानकारी थी।

सिविल सर्जन डॉ श्रीनिवास प्रसाद, जिला एड्स नियंत्रण पदाधिकारी डॉ अशोक कुमार और सदर अस्पताल अधीक्षक डॉ अनिल कुमार सिंह तक मामले की जानकारी पहुंचायी गयी थी। इसके बाद महिला को वार्ड में बेड उपलब्ध कराया गया और उपचार शुरू होने की बात सामने आयी, लेकिन प्रसव के लिए आवश्यक निर्णायक कदम नहीं उठाया जा सका। शनिवार को कराये गये अल्ट्रासाउंड में गर्भ में पानी की मात्रा 10.20 सेंटीमीटर दर्ज थी। रविवार को स्वास्थ्यकर्मियों ने परिजनों को बताया कि पानी का रिसाव होने के कारण इसकी मात्रा घटकर करीब पांच सेंटीमीटर रह गयी है। नर्सिंग स्टाफ की ओर से सिजेरियन की जरूरत बताये जाने के बावजूद प्रसूता को समय पर ऑपरेशन की सुविधा नहीं मिल सकी। यहां सवाल केवल एक प्रसूता के इलाज का नहीं, बल्कि एचआईवी संक्रमित गर्भवती महिलाओं और उनके नवजातों के लिए चलाये जा रहे सरकारी एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की जमीनी व्यवस्था का है। जब एचआईवी रिएक्टिव गर्भवती को सुरक्षित प्रसव की सुविधा ही सरकारी अस्पताल में नहीं मिल पाती, तो एचआईवी के मां से बच्चे में संक्रमण को रोकने की सरकारी मुहिम कितनी प्रभावी है? सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि यदि इस प्रसूता या उसके नवजात के साथ कोई अनहोनी होती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी बाद में नवजात के घर पहुंचकर उसे एचआईवी संक्रमण से बचाव की दवा देने की बात किस आधार पर करेंगे, जब प्रसव कराने वाली मां को ही सरकारी अस्पताल में सुरक्षित प्रसव की सुविधा उपलब्ध नहीं करायी जा सकी? मॉडल सदर अस्पताल में तीन मॉड्यूलर शल्य कक्ष होने और कुछ दिन पूर्व एचआईवी रिएक्टिव महिला का सिजेरियन होने के बावजूद इस मामले में कथित लापरवाही ने पूरी व्यवस्था को कठघरे में खड़ा कर दिया है। सरकार एचआईवी नियंत्रण और सुरक्षित मातृत्व पर करोड़ों रुपये खर्च कर रही है, लेकिन सीवान में एक गरीब एचआईवी रिएक्टिव प्रसूता को व्यवस्था के भरोसे छोड़ दिया जाना इन दावों की पोल खोलने के लिए काफी है। जिला एड्स नियंत्रण पदाधिकारी डॉ अशोक कुमार ने बताया कि हम पता लगा रहें हैं कि उस महिला ने किस अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया है। पता कर नवजात बच्चे को एचआईवी के संक्रमण से बचाव के लिए नेब्रापिन दवा 48 घंटे के अंदर पिलानी जरूरी होती है।

## एक नजर

### वर्ल्ड पैरा सीरीज में भारत के सात पदक पक्के, शीतल देवी फाइनल में

**अहमदाबाद,एजेंसी।** वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज 2026 के तीसरे दिन भारतीय तीरंदाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सात पदक पक्के कर लिए हैं। पैरा कंपाउंड महिला व्यक्तिगत स्पर्धा में शीतल देवी ने फाइनल में जगह बनाई है। फाइनल में 9 सितंबर को उनका सामना कजाखस्तान की ऐज़ादा सेइदान से होगा। व्यक्तिगत स्पर्धाओं में सरिता और तोमन कुमार कांस्य पदक के मुकाबले में पहुंचे हैं। रिकर्व महिला व्यक्तिगत में भावना और राजश्री धनराज राठौड़ के बीच कांस्य पदक का मुकाबला होगा, जिससे भारत का एक पदक और पक्का हो गया। डब्ल्यू1 महिला वर्ग में स्वाति चौधरी भी कांस्य के लिए खेलेंगी। टीम स्पर्धाओं में भारत ने तीनों पैरा रिकर्व वर्गों में पदक सुनिश्चित किया है। हरविंदर सिंह-विजय सुंडी पुरुष टीम में, भावना-पूजा महिला टीम में और हरविंदर-भावना मिक्स्ड टीम में फाइनल में पहुंचे। कंपाउंड पुरुष टीम में तोमन कुमार और श्याम सुंदर स्वामी फाइनल में हैं, जबकि शीतल-पायल की जोड़ी महिला टीम में कांस्य के लिए खेलेगी। डब्ल्यू1 मिक्स्ड टीम में आदिल अंसारी और स्वाति चौधरी भी फाइनल में पहुंच गए हैं। प्रतियोगिता के पदक मुकाबले 8 और 9 सितंबर को होंगे।

### सब जूनियर बालक अंतर मंडलीय प्रदेश स्तरीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 में प्रतिभाग करने के लिए मंडलीय टीम रवाना

**मुरादाबाद,एजेंसी।** ज़िला फुटबॉल एसोसिएशन मुरादाबाद के महासचिव मुहम्मद नासिर कमाल ने बताया कि सब जूनियर बालक अंतर मंडलीय प्रदेश स्तरीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 में प्रतिभाग करने के लिए मुरादाबाद मंडल की मंडलीय टीम सभी प्रकिया उपरांत आज जनपद आगरा के लिये रवाना हो गई। यह प्रतियोगिता आगरा में 8 सितंबर से 14 सितंबर तक आयोजित होगी। मुहम्मद नासिर कमाल ने आगे बताया कि उत्तर प्रदेश फुटबॉल संघ के महासचिव की निर्देशानुसार जूनियर बालक वर्ग का मंडल की टीम का चयन दो दिन पूर्व 5 सितम्बर को किया गया था। चयन उपरांत नियमानुसार चयनित खिलाडियों का सीआरएस किया गया। चयन समिति में ज़िला फुटबॉल एसोसिएशन के महासचिव मुहम्मद नासिर कमाल, स्पोर्ट्स ऑफिसर सुनील कुमार, कोच सचिन कुमार माधुरी देवी, आमिर मिर्ज़ा रहे। चयनित टीम में हार्दिक सिंह, कार्तिक कश्यप, बिलाल खान, ज़हरान, सार्थक गुप्ता, खतीब मुमताज़, अभ्युदय सिद्धार्थ, मुहम्मद ताज, वंश, निर्भय पाल, मो. फहाद राहत, रेहान अब्बास, मुहम्मद हाज़िक खान, मुहम्मद फरहान, वैभव, यश शामिल है। टीम मैनेजर के रुप में सचिन कुमार व टीम के कोच मारूफ अली रहेंगे।

### ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे श्रृंखला के लिए दक्षिण अफ्रीकी टीम घोषित, बावुमा और कोएत्जी की वापसी

**जोहान्सबर्ग,एजेंसी।** दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 24 सितंबर से शुरू होने वाली तीन मैचों की घरेलू वनडे श्रृंखला के लिए 16 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। टीम की कमान तेम्बा बावुमा संभालेंगे, जबकि तेज गेंदबाज गेराल्ड कोएत्जी की भी टीम में वापसी हुई है। बावुमा ने आखिरी बार दिसंबर, 2025 में भारत के खिलाफ वनडे मुकाबला खेला था। कोएत्जी 2023 विश्व कप के बाद पहली बार दक्षिण अफ्रीका की वनडे टीम में लौटे हैं। नामीबिया के खिलाफ हालिया श्रृंखला में आराम दिए गए नियमित खिलाड़ियों को भी टीम में शामिल किया गया है। इनमें एडेन मार्करम, मार्को यानसेन, लुंगी एनगिडी, डेविड मिलर, कॉर्बिन बॉश और क्विंटन डिकॉक शामिल हैं। मार्करम श्रृंखला के दूसरे और तीसरे वनडे के लिए उपलब्ध रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यह श्रृंखला अगले साल दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होने वाले वनडे विश्व कप की तैयारियों के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दोनों टीमें अक्टूबर में तीन मैचों की टेस्ट श्रृंखला में भी आमने-सामने होंगी। दक्षिण अफ्रीका ने अभी टेस्ट श्रृंखला के लिए अपनी टीम घोषित नहीं की है, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने सोमवार को ही अपनी टेस्ट टीम का ऐलान कर दिया था।

**दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम:**

तेम्बा बावुमा (कप्तान), ओटनील बार्टमैन, कॉर्बिन बॉश, मैथ्यू ब्रीट्जके, गेराल्ड कोएत्जी, क्विंटन डिकॉक, टोनी डी जोरजी, ब्योर्न फोर्टुइन, मार्को यानसेन, केशव महाराज, क्वेना मफाका, एडेन मार्करम, डेविड मिलर, लुंगी एनगिडी, रयान रिकेल्टन, ट्रिस्टन स्टब्स।

# दलीप ट्रॉफी फाइनल: ईशान किशन का तूफानी दोहरा शतक, ईस्ट जोन ने पहली पारी में बनाए 708 रन

**चेन्नई,एजेंसी।** कप्तान ईशान किशन की 270 रन की शानदार पारी और कुमार कुशाग्र के शतक की बदौलत ईस्ट जोन ने दलीप ट्रॉफी फाइनल में साउथ जोन के खिलाफ अपनी स्थिति बेहद मजबूत कर ली है। चेपॉक में मुकाबले के दूसरे दिन सोमवार को ईस्ट जोन की पहली पारी 708 रन पर समाप्त हुई। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में चेपॉक के मैदान पर यह तीसरा मौका है, जब किसी टीम ने 700 से अधिक रन बनाए हैं। 385 रन पर चार विकेट से आगे खेलने उतरी ईस्ट जोन की टीम ने दूसरे दिन भी शुरुआत से ही तेजी से रन बनाए। साउथ जोन ने एक ओवर के बाद ही नई गेंद ले ली, लेकिन मोहम्मद सिराज और एमडी निधीश विकेट हासिल नहीं कर सके। ईशान किशन ने सिराज के ओवर में लगातार चौके लगाकर शुरुआत की और निधीश को भी निशाना बनाया। कुमार कुशाग्र ने भी उनका साथ दिया और दोनों बल्लेबाजों ने साउथ जोन के गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा। त्रिपुराना विजय और श्रेयस गोपाल को स्पिन के लिए उतारा गया, लेकिन इसका भी कोई खास असर नहीं हुआ। कुशाग्र ने श्रेयस गोपाल की गेंद पर चौके लगाकर अपना छठा प्रथम श्रेणी शतक पूरा किया। वह 101 रन बनाकर आउट हुए।

कुशाग्र के आउट होने के बाद भी किशन ने आक्रामक अंदाज जारी रखा। उन्होंने श्रेयस गोपाल के एक ओवर में तीन चौके जड़े और महज 270 गेंदों में अपना दोहरा शतक पूरा किया। इसके बाद किशन ने तेजी से 250 रन का आंकड़ा पार किया और टीम को 600 रन के पार पहुंचाया। साउथ जोन को उम्मीद थी कि ईस्ट जोन जल्द पारी घोषित कर देगा, लेकिन किशन के इरादे कुछ और थे। थकान के कारण उन्हें कुछ समय के लिए रिटायर होना पड़ा। बाद में मोहम्मद शमी के 28 रन पर आउट होने के बाद किशन फिर मैदान पर लौटे और दुर्लभ तिहरा शतक पूरा करने की कोशिश की। हालांकि, दूसरे छोर पर लगातार विकेट गिरने के कारण किशन की तिहरे शतक की उम्मीद पूरी नहीं हो सकी। वह लॉन्ग ऑन के पास कैच देकर 270 रन पर आउट हुए और 300 रन से 30 रन दूर रह गए। उनकी पारी ने ईस्ट जोन को 708 रन के विशाल स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। 708 रन के जवाब में साउथ जोन के सामने अब थके हुए गेंदबाजों के बाद चुनौतीपूर्ण लक्ष्य है। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक ईस्ट जोन ने खिताब पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है।

## केविन पीटरसन बने इंग्लैंड की सीमित ओवर टीम के विशेषज्ञ मेंटर

**लंदन,एजेंसी।** इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन को 2027 वनडे विश्व कप तक इंग्लैंड की पुरुष सीमित ओवर टीम का विशेषज्ञ मेंटर नियुक्त किया गया है। उनकी पहली जिम्मेदारी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाला सीमित ओवर दौरा होगा, जिसके बाद टीम दक्षिण अफ्रीका का दौरा करेगी। पीटरसन इसके बाद पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू श्रृंखलाओं के दौरान भी टीम के साथ काम करेंगे। अगले 12 महीनों में वह विश्व कप की तैयारियों का हिस्सा रहेंगे। 2027 वनडे विश्व कप दक्षिण अफ्रीका में आयोजित होगा, जबकि जिम्बाब्वे और नामीबिया सह-मेजबान होंगे। दक्षिण अफ्रीका पीटरसन का जन्मस्थान भी है।

पीटरसन मुख्य कोच ब्रेंडन मैकुलम के कोचिंग दल का हिस्सा होंगे। इस दल में मार्कस ट्रेस्कोथिक, टिम साउदी, सारा टेलर और जीतन पटेल भी शामिल हैं। पीटरसन इससे पहले आईपीएल टीम दिल्ली कैपिटल्स के साथ मेंटर की भूमिका निभा चुके हैं। पीटरसन ने इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) के हवाले से कहा, 'मुझे बेहद गर्व है कि मुझे दक्षिण अफ्रीका में विश्व कप जीतने के सफर में इस टीम की मदद करने के लिए कहा गया है। 2014 के बाद पहली बार इंग्लैंड की जर्सी पहनना मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान और बेहद खास पल है। उन्होंने कहा, 'हमारे पास सीमित ओवर क्रिकेट की एक बेहद प्रतिभाशाली टीम है और मैं खिलाड़ियों के साथ कड़ी मेहनत करते हुए उनकी क्षमता को अधिकतम करने के लिए उत्साहित हूं। अगले 12 महीनों तक ब्रेंडन की रणनीतिक टीम का हिस्सा बनना शानदार अवसर है और मैं शुरुआत करने का इंतजार नहीं कर सकता।' मुख्य कोच मैकुलम ने पीटरसन का स्वागत करते हुए कहा, 'मेरे मन में केपी के लिए बहुत सम्मान है और क्रिकेट में उन्होंने जो हासिल किया है, उसका मैं बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। इंग्लैंड क्रिकेट पर उनका प्रभाव शानदार रहा है। उनके अनुभव, ज्ञान और कद का कोई व्यक्ति इस टीम के साथ भूमिका निभाना चाहता है, यह हमारे लिए शानदार है। उन्होंने कहा, 'मैं विशेष रूप से हमारे बल्लेबाजों के लिए उनके साथ काम करने के अवसर को लेकर उत्साहित हूं। केपी को इस बात की अनूठी समझ है कि उच्चतम स्तर पर प्रदर्शन करने के लिए क्या करना पड़ता है और यह हमारे खिलाड़ियों के लिए बेहद उपयोगी होगा।

## महिला एशिया कप: पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना पर लगा जुर्माना

**दुबई।** पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम की कप्तान फातिमा सना पर भारत के खिलाफ महिला एशिया कप मुकाबले के दौरान शैफाली वर्मा को आउट करने के बाद विदाई इशारा (सेंड ऑफ) करने के लिए मैच फीस का 10 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है। इसके साथ ही उनके खाते में एक डिमेरिट अंक भी जोड़ा गया है।

फातिमा को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की आचार संहिता के स्तर-1 के उल्लंघन का दोषी पाया गया। उन्होंने अनुच्छेद 2.5 का उल्लंघन किया, जो बल्लेबाज के आउट होने के बाद ऐसे शब्दों, हरकतों या इशारों से संबंधित है, जो उसे अपमानित करें या आक्रामक प्रतिक्रिया के लिए उकसा सकते हैं। यह घटना भारत की पारी के दौरान शैफाली वर्मा के आउट होने के बाद हुई। फातिमा ने शैफाली का कैच लेने के बाद पवेलियन की ओर इशारा किया था। यह 24 महीने की अवधि में फातिमा का दूसरा अपराध है। इसके साथ ही उनके डिमेरिट अंकों की संख्या बढ़कर दो हो गई है। इससे पहले उन्हें 6 अगस्त 2025 को डबलिन में आयरलैंड के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले के दौरान एक डिमेरिट अंक मिला था। भारत के खिलाफ पाकिस्तानी टीम के केवल 55 रन पर सिमटने के बावजूद फातिमा ने गेंद से प्रभावी प्रदर्शन किया था। उन्होंने तीन विकेट लिए थे। 56 रन के लक्ष्य का पीछा करते समय आक्रामक शुरुआत करने वाली शैफाली उनकी पहली शिकार बनी थीं। शैफाली ने फातिमा की छठी गेंद पर आसान कैच गेंदबाज को ही दे दिया था। फातिमा ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और मैच रेफरी सुप्रिया दास द्वारा प्रस्तावित सजा को स्वीकार कर लिया। इसलिए औपचारिक सुनवाई की जरूरत नहीं पड़ी। आचार संहिता के स्तर-1 के उल्लंघन में न्यूनतम सजा आधिकारिक फटकार है, जबकि अधिकतम सजा मैच फीस का 50 प्रतिशत जुर्माना और एक या दो डिमेरिट अंक हो सकती है। भारत से 7 विकेट की मिली हार के बाद पाकिस्तान के पास संभलने के लिए ज्यादा समय नहीं है। उसका अगला मुकाबला सोमवार को हांगकांग, चीन के खिलाफ होगा। इस मुकाबले में जीत पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचा देगी।

# एशियन गेम्स के लिए झारखंड की साइकिलिस्ट सरिता कुमारी का भारतीय टीम में चयन

**रांची,एजेंसी।** जापान के नागोया शहर में 19 सितंबर से चार अक्टूबर 2026 तक आयोजित होने वाले 20वें एशियन गेम्स के लिए झारखंड की प्रतिभाशाली साइकिलिस्ट सरिता कुमारी का चयन भारतीय साइकिलिंग टीम में हुआ है। सरिता के चयन से झारखंड के खेल जगत में खुशी और उत्साह का माहौल है। वह एशियन गेम्स जैसे प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय खेल मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। यह जानकारी सोमवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति में झारखंड साइकिलिंग संघ के महासचिव शैलेंद्र कुमार पाठक ने दी। उन्होंने बताया कि सरिता कुमारी ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की विभिन्न साइकिलिंग प्रतियोगिताओं में लगातार बेहतर प्रदर्शन करते हुए अपनी प्रतिभा और क्षमता साबित की है। उनकी मेहनत, अनुशासन और लगातार प्रभावी प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें भारतीय टीम में स्थान मिला है।

झारखंड साइकिलिंग संघ ने सरिता के चयन को राज्य में साइकिलिंग खेल के बढ़ते स्तर और यहां के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिल रही पहचान का महत्वपूर्ण प्रमाण बताया है। संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि सरिता का चयन झारखंड के उभरते साइकिलिस्टों के लिए भी प्रेरणादायक है। संघ ने उम्मीद जताई कि सरिता कुमारी एशियन गेम्स में अपने प्रदर्शन से देश और झारखंड का नाम रोशन करेंगी। संघ के पदाधिकारियों ने उनके उज्ज्वल प्रदर्शन की कामना करते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करना उनके खेल करियर की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सरिता के भारतीय टीम में चयन पर राजमहल सांसद विजय हांसदा, राज्य के खेल सचिव मुकेश कुमार, खेल निदेशक छवि रंजन, पर्यटन निदेशक नमन प्रियेश लकड़ा, झारखंड साइकिलिंग संघ के अध्यक्ष मधुकांत पाठक, महासचिव शैलेंद्र पाठक, कोषाध्यक्ष रणवीर सिंह, उपाध्यक्ष अम्लान कुसुम सिन्हा सहित संघ के अन्य पदाधिकारियों, प्रशिक्षकों और खेलप्रेमियों ने उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं।

# नाइजीरिया ने जिम्बाब्वे को हराकर किया अंडर-19 महिला टी20 विश्वकप के लिए क्वालीफाई

**दार एस सलाम,एजेंसी।** नाइजीरिया ने रोमांचक मुकाबले में जिम्बाब्वे को चार रन से हराकर अंडर-19 महिला टी20 विश्व कप अफ्रीका क्वालीफायर का खिताब जीत लिया और अगले साल होने वाले मुख्य टूर्नामेंट के लिए क्वालीफाई कर लिया। नाइजीरिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए छह विकेट पर 98 रन बनाए। इसके जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 19.5 ओवर में 94 रन पर सिमट गई। इस जीत के साथ नाइजीरिया ने क्वालीफायर अभियान में अपना अजेय रिकॉर्ड कायम रखा और अगले साल बांग्लादेश और नेपाल में होने वाले अंडर-19 महिला टी20 विश्व कप के लिए क्वालीफाई करने वाली अफ्रीका की दूसरी टीम बन गई। दक्षिण अफ्रीका पहले ही जगह बना चुका है। नाइजीरिया की कप्तान 17 वर्षीय क्रिस्टाबेल चुकवुओन्ये ने कहा, 'मैच खत्म होने के बाद मैं रो पड़ी, क्योंकि मैं वास्तव में अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रही थी। अगला चरण अभी शुरुआत है और हम जानते हैं कि वहां चुनौती और कठिन होगी। मेरी टीम ने वास्तव में शानदार प्रदर्शन किया है।

उन्होंने कहा, 'खिलाड़ियों ने कोचों की बात मानी, एकजुट रहीं और आखिरी ओवर में दबाव के बावजूद अपना संयम बनाए रखा। मैं इस ट्रॉफी को हाथ में लेकर यहां नहीं होती अगर मुझे कोचिंग स्टाफ और अपनी खिलाड़ियों का समर्थन नहीं मिला होता। मैं उन सभी की बहुत आभारी हूं। चुकवुओन्ये ने छठे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 21 रन बनाए और टीम को 98 रन तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। नाइजीरिया की पारी में तीन रन आउट भी हुए। इसके बाद उसैन पीस ने जिम्बाब्वे के शीर्ष क्रम को अकेले ही झकझोर दिया और लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम को शुरुआती झटके दिए। बाद में नाइजीरिया की अन्य गेंदबाजों ने भी योगदान दिया और जिम्बाब्वे को 94 रन पर समेट दिया। यह दूसरा मौका है जब नाइजीरिया ने अंडर-19 महिला टी20 विश्व कप के लिए क्वालीफाई किया है। इससे पहले टीम 2025 में भी विश्व कप में खेली थी। उस संस्करण में नाइजीरिया ने तीन पूरे हुए मुकाबलों में दो जीत दर्ज की थीं, जबकि दो मुकाबले बारिश के कारण धुल गए थे। उसका सबसे यादगार प्रदर्शन न्यूजीलैंड के खिलाफ रहा था, जहां नाइजीरिया ने बारिश से प्रभावित मुकाबले में 65 रन का बचाव करते हुए जीत हासिल की थी। नाइजीरिया के अलावा अमेरिका ने अमेरिका क्षेत्र, समोआ ने पूर्वी एशिया-प्रशांत क्षेत्र और संयुक्त अरब अमीरात ने एशिया क्षेत्र के क्वालीफिकेशन मार्ग से अगले साल के टूर्नामेंट में जगह बनाई है।

## प्रीमियर लीग के तीसरे सप्ताह में हालांड के 300 गोल और आर्सेनल का परफेक्ट रिकॉर्ड सुर्खियों में

**लंदन।** प्रीमियर लीग फुटबॉल 2026-27 सत्र के तीसरे सप्ताह में कई ऐतिहासिक उपलब्धियां और रोमांचक मुकाबले देखने को मिले। एलेक्जेंडर इसाक ने लिवरपूल के लिए शानदार शुरुआत की, एर्लिंग हालांड ने क्लब फुटबॉल में 300 गोल पूरे किए, आर्सेनल ने लगातार तीसरी जीत दर्ज कर अपना शत-प्रतिशत रिकॉर्ड कायम रखा, जबकि न्यूकैसल ने दो गोल से पिछड़ने के बाद बोर्नमाउथ के खिलाफ शानदार वापसी की।

मैनचेस्टर सिटी की ओर से कोवेंट्री सिटी के खिलाफ निर्णायक गोल कर एर्लिंग हालांड ने शीर्ष स्तर के क्लब फुटबॉल में 300 गोल पूरे कर लिए। उन्होंने यह उपलब्धि 368वें मुकाबले में हासिल की। प्रीमियर लीग में यह उनका 20वां हेडर से किया गया गोल भी था। मैनचेस्टर सिटी के किसी खिलाड़ी के लिए प्रतियोगिता में हेडर से किए गए सबसे ज्यादा गोल हैं। मैनचेस्टर सिटी ने सत्र के शुरुआती तीनों प्रीमियर लीग मुकाबले जीत लिए हैं। क्लब ने आठवीं बार ऐसा किया है, जबकि चेल्सी ने इससे ज्यादा बार यह उपलब्धि हासिल की है। एलेक्जेंडर इसाक ने लिवरपूल की ओर से इप्सविच टाउन के खिलाफ 2-0 की जीत में शुरुआती नौ मिनट के भीतर दो गोल दागकर शानदार प्रभाव छोड़ा। 2011 के बाद यह पहली बार है जब लिवरपूल के किसी खिलाड़ी ने प्रीमियर लीग मुकाबले में इतनी जल्दी दो गोल किए हैं। दोनों गोल में कोडी गाक्पो ने सहायता की। वह 1998 के बाद पहले ऐसे खिलाड़ी बने, जिन्होंने प्रीमियर लीग मुकाबले के शुरुआती नौ मिनट में एक ही साथी खिलाड़ी के दो गोल में सहायता की। इसाक ने 2024-25 सत्र की शुरुआत से पोर्टमैन रोड पर प्रीमियर लीग में पांच गोल किए हैं, जो इस अवधि में किसी एक प्रतिद्वंद्वी के मैदान पर संयुक्त रूप से सर्वाधिक हैं।

आर्सेनल ने पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए चेल्सी को 2-1 से हराया और सत्र में लगातार तीसरी जीत दर्ज की। मार्टिन ओडेगार्ड ने इस सत्र में सभी प्रतियोगिताओं में चार मुकाबलों में तीन गोल कर लिए हैं। पिछले सत्र में 36 मुकाबलों में वह केवल एक गोल कर सके थे। आर्सेनल की इस जीत ने चेल्सी के खिलाफ प्रीमियर लीग में पीछे होने के बाद जीत दर्ज न कर पाने का 14 मुकाबलों का सिलसिला भी खत्म किया। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने शुरुआती तीनों लीग मुकाबलों में कम-से-कम दो गोल खाए हैं। पिछले 50 वर्षों में यह केवल दूसरी बार है जब टीम ने किसी लीग सत्र की शुरुआत लगातार तीन मुकाबलों में दो या उससे अधिक गोल खाने के साथ की है। एवर्टन के खिलाफ मुकाबले में ब्रायन मबेउमो ने दूसरे हाफ की शुरुआत के महज 46 सेकंड बाद गोल किया। हालांकि, मेजबान टीम के लिए एंसले मैटलैंड-नाइल्स ने 95वें मिनट में गोल कर मुकाबला बराबरी पर खत्म कराया। न्यूकैसल ने दो गोल से पिछड़ने के बाद बोर्नमाउथ के खिलाफ 2-2 से ड्रॉ खेला। टीम ने मार्च 2024 के बाद पहली बार दो या उससे अधिक गोल से पिछड़ने के बाद हार से बचने में सफलता हासिल की। इस मुकाबले से पहले न्यूकैसल दो या उससे अधिक गोल से पिछड़ने वाले अपने पिछले 15 प्रीमियर लीग मुकाबले हार चुका था। वहीं, बोर्नमाउथ ने एक अनचाहा रिकॉर्ड बनाया। वह प्रीमियर लीग इतिहास की पहली टीम बन गई, जिसने सत्र के शुरुआती तीनों मुकाबलों में पहला गोल करने के बावजूद एक भी मैच नहीं जीता।

## एक नजर

### बलूचिस्तान में छह अज्ञात शव मिलने से हड़कंप, लापता युवाओं से जुड़े होने की आशंका

**क्वेटा,एजेंसी।** पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के मस्तुंग जिले में सोमवार को दो अलग-अलग स्थानों से छह अज्ञात शव मिलने के बाद इलाके में चिंता बढ़ गई। मानवाधिकार संगठन बलूच वॉइस फॉर जस्टिस (बीवीजे) ने आशंका जताई है कि इनमें कुछ ऐसे बलूच युवक भी हो सकते हैं, जिन्हें पहले कथित तौर पर जबरन लापता किया गया था। संगठन के अनुसार, शवों पर कथित तौर पर यातना के निशान दिखाई दिए। बीवीजे का दावा है कि शवों को पुलिस अधिकारी अब्दुल रऊफ बलूच की निगरानी में कुछ समय बाद वहां से हटाया गया और अस्पताल ले जाया गया। बाद में उन्हें क्वेटा ले जाने तथा फिर वापस उसी स्थान पर छोड़ने की भी बात कही गई है।

इस बीच स्थानीय मीडिया के अनुसार, मस्तुंग के खड़कोचा इलाके में पाकिस्तानी बलों की ड्रोन कार्रवाई में एक बच्चे समेत कम से कम तीन लोग घायल हुए। रविवार को गैरो इलाके में हुए हमले के बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। मानवाधिकार संगठन ने बलूचिस्तान में नागरिकों के कथित जबरन गायब होने और हिरासत में यातना दिए जाने के आरोप लगाए हैं। उसने संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों से छह शवों की तत्काल एवं पारदर्शी जांच कराने, मृतकों की पहचान करने और यह पता लगाने की मांग की है कि क्या वे पहले लापता किए गए लोगों में शामिल थे।

### भारतीय बचाव दल द्वारा चिलिमे हाइड्रोपावर में रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी

**काठमांडू,एजेंसी।** नेपाल के लिए भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने बताया है कि रसुवा स्थित चिलिमे जलविद्युत परियोजना में बचाव कार्य लगातार जारी है। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी दी कि भारतीय टीम सहित समन्वय के साथ लगातार बचाव

के प्रयास किए जा रहे हैं। राजदूत श्रीवास्तव के अनुसार, नेपाल और भारत की संयुक्त तकनीकी टीम ने सुरंग के अंदर प्रवेश करने के लिए आवश्यक सुरक्षा रस्सी का कनेक्शन तैयार कर लिया है। उन्होंने कहा, 'सुरंग के अंदर जमा कीचड़ और गाद हटाने के लिए बड़ी क्षमता वाला मड पंप और जनरेटर भी घटनास्थल पर लाया गया है। इस बीच, बचाव अभियान को आसान बनाने के लिए आवश्यक सड़क निर्माण का काम भी आगे बढ़ाया जा रहा है।

### यूक्रेन ने नाटो से एयर डिफेंस सिस्टम की आपूर्ति तेज करने की अपील की

**ब्रसेल्स।** यूक्रेन ने रूस के संभावित ड्रोन और मिसाइल हमलों से निपटने के लिए नाटो सहयोगियों से वायु और मिसाइल रक्षा प्रणालियों की आपूर्ति में तेजी लाने की अपील की है। यह मांग मंगलवार को होने वाली यूक्रेन रक्षा संपर्क समूह की 'रामस्टीन' बैठक से पहले उठाई गई है। ब्रसेल्स में सोमवार को आयोजित नाटो-यूक्रेन परिषद की विशेष बैठक में यूक्रेनी अधिकारियों ने रूस से मौजूदा हवाई खतरे का आकलन पेश किया और तत्काल आवश्यक एयर डिफेंस उपकरणों की सूची सहयोगी देशों के सामने रखी। बैठक की अध्यक्षता नाटो महासचिव मार्क रूटे ने की। यूक्रेन के उप रक्षा मंत्री सेरही बोयेव ने कहा कि उनके देश को मदद अभी और तत्काल चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि हथियारों की कुल संख्या से अधिक महत्वपूर्ण उनकी समय पर आपूर्ति है, क्योंकि यूक्रेन को आगामी सर्दियों में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों का सामना करने की तैयारी करनी है। यूक्रेन ने सहयोगी देशों से वर्ष के अंत तक सैन्य सहायता के लिए नाटो के निर्धारित 70 अरब यूरो के लक्ष्य को पूरा करने के लिए आवश्यक संसाधन जुटाने का भी आग्रह किया है। इसमें 2026 के लिए यूरोपीय संघ के यूक्रेन सहायता ऋण से सैन्य मदद के लिए निर्धारित 28.3 अरब यूरो भी शामिल हैं। मंगलवार को होने वाली रामस्टीन बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए होगी। इसमें नाटो और यूरोपीय देशों के वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। बैठक में एयर और मिसाइल डिफेंस सहयोग का प्रमुख मुद्दा बने रहने की संभावना है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की लंबे समय से अमेरिकी पैट्रियट मिसाइलों की आपूर्ति बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। यूक्रेन का अनुमान है कि उसे वर्ष के अंत तक करीब 300 इंटरसेप्टर की जरूरत पड़ सकती है।

# अमेरिका के मियामी एयरपोर्ट पर कार्गो विमान दुर्घटनाग्रस्त, पांच की मौत

**वाशिंगटन,एजेंसी।** अमेरिका के मियामी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रविवार को अमेजन का मालवाहक (कार्गो) विमान रनवे से बाहर निकल कर खेत में पहुंच गया। विमान ने कई वाहनों को टक्कर मारी और उसमें आग लग गई। अधिकारियों के मुताबिक, हादसे में कम से कम पांच लोगों की मौत हुई। तीन लोग गंभीर रूप से घायल हैं। दो अन्य लोगों को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि हादसे के बाद एयरपोर्ट पर लगभग तीन घंटे तक विमानों की आवाजाही रोक दी गई। सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारियों ने हादसे के बाद संवाददाता सम्मेलन में बताया कि मालवाहक विमान दोपहर करीब 2 बजे (स्थानीय समय) रनवे से बाहर निकल गया। यह विमान प्यूर्टो रिको के सैन जुआन से मियामी पहुंचा था। अधिकारियों ने कहा कि अभी यह पता नहीं चल पाया है कि मरने वाले लोग विमान में सवार थे या उन वाहनों में थे, जिन्हें विमान ने टक्कर मारी। हादसे के बाद आसमान में काला धुआं छा गया। मियामी-डेड रेस्क्यू फायर चीफ रे जदल्लाह ने बताया कि विमान के कॉकपिट में पायलट और को-पायलट फंस गए थे। कुछ लोग कारों के अंदर भी फंसे थे। एक अन्य व्यक्ति वाहन के नीचे दब गया था।

हादसे के बाद मियामी हवाई अड्डे पर लगभग तीन घंटें तक उड़ानें रोक दी गईं। विमान से ईंधन भी लीक हो रहा था। हादसे के कई घंटे बाद तक दमकलकर्मी इस लीकेज को संभालने में जुटे थे। हादसे के बाद प्राइम एयर का यह

विमान सड़क के किनारे जाकर रुक गया। वहां दो बड़े ट्रक भी खड़े थे। मौके की तस्वीरों में विमान पेट के बल पड़ा दिखाई दिया। आग लगने के बावजूद विमान का ज्यादातर हिस्सा सुरक्षित रहा। यह विमान 32 साल पुराना बोइंग 767 है। इसे पहले यात्रियों को ले जाने के लिए बनाया गया था। दो दशक से ज्यादा समय तक यह कई एयरलाइंस के लिए उड़ा। 2015 में इसे कार्गो विमान में बदल दिया गया था। यह उड़ान नॉर्थ कैरोलिना की कार्गो कंपनी 21 एयर ने संचालित की थी। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइटअवेयर के मुताबिक रविवार दोपहर बाद हवाई अड्डे पर करीब 250 उड़ानें लेट हुईं। राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड (एनटीएसबी) ने जांच के लिए अपनी टीम मियामी भेजने की बात कही है। टीम का नेतृत्व इसकी अध्यक्ष जेनिफर होमेंडी करेंगी। अमेजन की प्रवक्ता केली नेंटेल ने कहा कि वह जांच में पूरा सहयोग करेगा। कंपनी ने हादसे में पांच लोगों की मौत पर दुख जताया। अमेजन ने मृतकों के परिवारों, उनके करीबियों और हादसे से प्रभावित सभी लोगों के प्रति संवेदना जताई।

## ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज ने नेपाल में विनाशकारी बाढ़ पर जताया गहरा दुख

**काठमांडू।** ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि इस मुश्किल दौर में ऑस्ट्रेलिया नेपाल के साथ खड़ा है। ऑस्ट्रेलियाई संसद को संबोधित करते हुए अल्बनीज़ ने बताया कि आपदा के बाद 36 ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों का अब तक पता नहीं चल पाया है। उन्होंने लापता लोगों के परिवारों और रिश्तेदारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उम्मीद जताई कि उन्हें जल्द खोजकर सुरक्षित निकाला जाएगा। नेपाल में सोमवार को आपदा में जान गंवाने वाले लोगों की याद में राष्ट्रीय शोक दिवस मनाए जाने के दौरान अल्बनीज़ ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए भी मृतकों के परिवारों और बाढ़ से प्रभावित सभी लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। अल्बनीज़ ने पिछले शुक्रवार को नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह से फोन पर बातचीत भी की थी। इस दौरान दोनों नेताओं ने आपदा के बाद की स्थिति पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि संकट से निपटने के लिए ऑस्ट्रेलियाई सरकार ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले नेपाली, तिब्बती और भारतीय समुदायों के साथ भी करीबी समन्वय बनाए हुए है।

## सर्बिया में जल्द होंगे मध्यावधि चुनाव, प्रधानमंत्री ने संसद भंग करने का प्रस्ताव दिया

**बेलग्रेड।** सर्बिया के प्रधानमंत्री ज्यूरो मैकुट ने सोमवार को संसद भंग करने की औपचारिक सिफारिश कर दी। इसके साथ ही देश में अक्टूबर में मध्यावधि संसदीय चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया है। यह फैसला करीब दो वर्षों से जारी राजनीतिक अस्थिरता और बड़े पैमाने पर हो रहे प्रदर्शनों के बीच लिया गया है। मैकुट ने सरकार की विशेष बैठक के बाद टेलीविजन प्रसारण में कहा कि चुनाव लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने और राजनीतिक तनाव कम करने में मदद करेंगे। अब राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुचिच के पास संसद भंग करने के प्रस्ताव पर निर्णय लेने के लिए 72 घंटे का समय है।

सर्बिया में मौजूदा राजनीतिक संकट की शुरुआत नवंबर 2024 में नोवी साद रेलवे स्टेशन की छतरी गिरने की घटना के बाद हुई थी। हादसे में 16 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद छात्रों के नेतृत्व में देशभर में सरकार विरोधी प्रदर्शन शुरू हुए। प्रदर्शनकारी इस मामले में जवाबदेही और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। छात्र आंदोलन ने आगामी चुनाव में उतरने की घोषणा की है, जिससे सत्तारूढ़ सर्बियन प्रोग्रेसिव पार्टी (एसएनएस) के सामने मजबूत चुनौती खड़ी हो सकती है। एसएनएस 'यूनाइटेड सर्बिया' नाम से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। यूरोपीय संघ भी चुनाव पर करीबी नजर रखेगा। सर्बिया की ईयू सदस्यता प्रक्रिया कानून के शासन, मीडिया स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मानकों को लेकर चिंताओं के बीच पहले ही धीमी पड़ी है। रूस के खिलाफ ईयू प्रतिबंधों से दूरी बनाए रखना भी बेलग्रेड और ब्रसेल्स के बीच तनाव का कारण है।

# नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 1,355 पहुंची, करीब 5,000 लोग अब भी लापता

**काठमांडू,एजेंसी।** नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या 1,355 पहुंच गई है। अभी भी जारी खोज, बचाव और राहत अभियान के बीच करीब 5,000 लोग अब भी लापता या लापता बताए जा रहे हैं।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार बरामद अवशेषों में मानव शरीर के विभिन्न अंग भी शामिल हैं। अब तक 98 शवों की पहचान कर उन्हें उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। प्राधिकरण की प्रवक्ता शांति महत ने बताया कि रसुवा से 169, नुवाकोट से 197, धादिङ से 70, गोरखा से 75, तनहूं से 38, चितवन से 363, नवलपरासी पूर्व से 222 और नवलपरासी पश्चिम से 221 शव बरामद किए गए हैं। उन्होंने बताया कि बाढ़ के बाद करीब 4,996 लोगों के लापता होने या उनका पता नहीं चल पाने की सूचना है। नवीनतम रिकॉर्ड के अनुसार एक प्रभावित क्षेत्र में करीब 1,967 लापता लोगों और नुवाकोट में करीब 2,340 लोगों का विवरण अपडेट किया गया है। प्राधिकरण के अनुसार लापता लोगों में करीब 100 सुरक्षाकर्मी और सरकारी कर्मचारी तथा लगभग 589 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। इस बीच, बाढ़ के कारण फंसे 13,396 लोगों को अब तक सुरक्षित बचाया जा चुका है। नेपाल विद्युत प्राधिकरण के अनुसार बाढ़ में घायल 6,672 लोगों का इलाज कराया गया है। इनमें से 323 लोग अभी भी विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन हैं, जबकि 228 लोगों को अस्पताल से छुट्टी देकर घर भेज दिया गया है। वर्तमान में बाढ़ प्रभावित 3,533 लोग 39 होल्डिंग सेंटरों में रह रहे हैं। प्राधिकरण के अनुसार इनमें 669 लोग रसुवा, 2,651 नुवाकोट और 213 लोग धादिङ में हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में खोज एवं बचाव, राहत वितरण और सुरक्षा व्यवस्था के लिए कुल 21,402 सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है। इनमें 9,287 नेपाली सेना, 7,912 नेपाल पुलिस और 4,203 सशस्त्र पुलिस बल के जवान शामिल हैं।

# नेपाल में बाढ़ के बाद सुरंगों में फंसे लोगों का बचाव अभियान बना जटिल

**काठमांडू,एजेंसी।** नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के बाद सुरंगों के भीतर फंसे लोगों को बचाने का अभियान लगातार जटिल होता जा रहा है। अलग-अलग स्थानों पर एक साथ कई संभावित बचाव अभियान चलाने पड़ रहे हैं, जिनमें अलग-अलग जोखिम, अनिश्चितताएं और चुनौतियां मौजूद हैं।

बचाव अभियान का नेतृत्व कर रहे 62 वर्षीय ऑस्ट्रेलियाई सुरंग विशेषज्ञ और भूविज्ञानी प्रोफेसर अर्नोल्ड डिक्स ने कहा कि नेपाल इस समय एक असाधारण स्थिति का सामना कर रहा है, जहां कई संभावित बचाव अभियान एक साथ सामने हैं। भारत के उत्तराखंड में वर्ष 2023 में सिल्क्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों के सफल बचाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर अंतरराष्ट्रीय पहचान हासिल करने वाले डिक्स ने नेपाल की मौजूदा स्थिति को अपने जीवन की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक बताया। सोमवार को सोशल मीडिया पर सिल्क्यारा बचाव अभियान को याद करते हुए उन्होंने कहा कि 41 श्रमिकों का सफल बचाव इस बात का प्रमाण था कि सामूहिक प्रयास से असंभव जैसी दिखने वाली चुनौतियों को भी पूरा किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि एक बड़ी चुनौती को पार कर लेना जरूरी नहीं कि सभी परीक्षाएं खत्म हो गई हों। इसके बजाय इससे और बड़ी जिम्मेदारियां सामने आ सकती हैं। पश्चिमी अवधारणा में

कर्तव्य और पूर्वी दर्शन में धर्म के बीच समानता बताते हुए डिक्स ने कहा कि बचाव अभियान में प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि सफलता की संभावना कितनी भी अनिश्चित क्यों न हो, सही काम करना जारी रखा जाए। उन्होंने कहा कि सिल्क्यारा बचाव अभियान ने उन्हें यह सीख दी कि किसी चीज के मुश्किल या असंभव जैसी दिखने को वास्तव में असंभव नहीं समझना चाहिए। वहीं, नेपाल की मौजूदा स्थिति उन्हें एक और महत्वपूर्ण सबक सिखा रही है—जब एक ही समय में कई लोगों की जिंदगी बचाव दलों पर निर्भर हो सकती है, तो उम्मीद को अनुशासित कार्रवाई में और संवेदना को व्यावहारिक सहायता में बदलना जरूरी है। डिक्स के अनुसार किसी बचाव अभियान की असली परीक्षा केवल इस बात से नहीं होती कि कितनी जानें बचाई गईं, बल्कि इस बात से होती है कि परिस्थितियां कठिन होने, जिम्मेदारियां बढ़ने और परिणाम अनिश्चित रहने के बावजूद बचाव दल अपने प्रयास जारी रखते हैं या नहीं। डिक्स ने जोर देकर कहा कि किसी बचाव अभियान की सफलता का आकलन केवल बचाई गई जिंदगियों की संख्या से नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने उन लोगों की तलाश और सहायता जारी रखने की जिम्मेदारी पर जोर दिया, जो अभी भी जीवित हो सकते हैं। उनके संदेश ने पूर्वी नेपाल में आए 6.9 तीव्रता के भूकंप के दौरान बचाव अभियानों का अनुभव करने वाले लोगों की पुरानी यादें भी ताजा कर दी हैं। कुछ लोगों ने कहा कि डिक्स के विचारों ने उन्हें पिछली आपदाओं की याद दिलाने के साथ-साथ मौजूदा संकट के बीच नई उम्मीद भी जगाई है।

## राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने नेपाल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया

**काठमांडू।** नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने भोटेकोशी बाढ़ से प्रभावित नुवाकोट जिले के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान राष्ट्रपति पौडेल को जिला आपदा प्रबंधन समिति ने प्रभावित क्षेत्रों में जारी खोज एवं बचाव अभियान, राहत वितरण, होल्डिंग सेंटरों के प्रबंधन तथा पुनर्वास प्रयासों के बारे में जानकारी दी। मुख्य जिला अधिकारी शम्भु प्रसाद रेग्मी और समिति के अन्य सदस्यों ने राष्ट्रपति को जिले में बाढ़ से हुई जन-धन की क्षति के बारे में जानकारी दी। रेग्मी ने खोज एवं बचाव, राहत वितरण, प्रभावित समुदायों के पुनर्वास तथा तत्काल पुनर्निर्माण के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में भी बताया। राष्ट्रपति पौडेल ने विदुर नगरपालिका-2 स्थित कवर हॉल में बनाए गए होल्डिंग सेंटर का भी निरीक्षण किया। वहां उन्होंने रसुवा और नुवाकोट के बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की, जो इस केंद्र में शरण लिए हुए हैं। बातचीत के दौरान प्रभावित लोगों ने विनाशकारी भोटेकोशी बाढ़ से हुए नुकसान और तबाही के बारे में राष्ट्रपति को जानकारी दी। उन्होंने सरकार और संबंधित संस्थाओं से खोज एवं बचाव, राहत वितरण और पुनर्वास कार्यों में तेजी लाने के साथ-साथ भविष्य में ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए तैयारियों को और मजबूत करने की मांग की।

## एक नजर

### सरकार अल्पसंख्यकों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है : नसीमुद्दीन

**सहरसा।** अल्पसंख्यक अधिकार मंच के राज्यव्यापी आहवान पर सहरसा स्टेडियम के बाहरी हिस्से में अल्पसंख्यकों द्वारा अपने अधिकारों की रक्षा हेतु एक दिवसीय घरना दिया गया। अल्पसंख्यक अधिकार मंच के संयोजक मोहम्मद तौहीद आलम की अध्यक्षता में चले धरनार्थियों को संबोधित कर अल्पसंख्यक अधिकार मंच के नेता नसीमुद्दीन ने कहा केन्द्र एवं राज्य सरकार अल्पसंख्यकों के साथ सतौला व्यवहार कर रही है। संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को खत्म कर रही है तथा भेदभाव भी कर रही है।वक्फ कानून में संशोधन कर अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय किया जा रहा है।सच्चर एवं रंगनाथ मिश्र आयोग के सिफारिशों को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। अल्पसंख्यकों के नाम पर नफरत फैलाया जा रहा है और बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के नाम पर राजनीति रोटी सेकी जा रही है। अन्य वक्ताओं ने सरकार के दोहरे मापदंड और अल्पसंख्यकों अधिकार पर रोज नये हमले की निन्दा करते साम्प्रदायिक,भड़काऊ एवं कौमी एकता को खंडित करने वाले भाषणों पर रोक लगाने की बात कही। मदरसों में आधुनिक, तकनीकी एवं रोजगारोन्मुखी शिक्षा व्यवस्था लागू करने की मांग किया।धरना का पुरजोर समर्थन करते सीपीएम जिला सचिव कॉ. रणधीर यादव ने कहा केन्द्र एवं राज्य दोनों ही सरकारें जनता के मुलभूत समस्याओं की अनदेखी कर धर्म मजहब की राजनीति करती है। मंहगाई बेरोजगारी और भ्रष्टाचारी से आमजन त्राहिमाम है और देश में हिन्दू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद का उन्माद पैदा कर राजनीति की जा रही है जो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के अच्छा नहीं है। धरना को अल्पसंख्यक अधिकार मंच के नेता प्रोफेसर ए.आर.रहमान,नसीम मिस्त्री, मुर्शीद आलम,नौशाद आलम, रेहान खां उर्फ रिंकू, अमीर खां, असफाक अंसारी, मोहम्मद कारी, मोहम्मद जुबेर, जफ्फर इमाम, मोहम्मद मंसुर आलम, मकसूद आलम,सोनी खातुन, जसीमा खातून आदि ने संबोधित किया। सभा के अन्त में प्रतिनिधिमंडल द्वारा अपनी 13 सूत्री मांगों के स्मार पत्र जिला पदाधिकारी सहरसा को समर्पित कर आवश्यक कार्यवाही हेतु आग्रह किया।

### सुदिव्य सोनू के अधूरे सपने को करेंगे मिलकर पूरा : इरफान

**धनबाद।** स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने दिवंगत मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू के निधन पर गहरा दुख जताया है। असर्फी अस्पताल में इलाजरत अपने रिश्तेदार से मिलने पहुंचे मंत्री ने सोमवार को कहा कि सुदिव्य सोनू के जाने से जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। वहीं एसएनएमएमसीएच के सर्जिकल आईसीयू में बिजली नहीं रहने से महिला की मौत के मामले पर मंत्री ने मीडिया में चल रही खबरों को दुष्प्रचार बताया। इसके साथ ही छात्रों के आंदोलन को लेकर भाजपा के राज्यव्यापी आंदोलन पर भी उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने सुदिव्य कुमार सोनू के निधन को झारखंड के लिए बड़ा सदमा बताया। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने भाई और एक ऐसे साथी को खो दिया है, जो हमेशा सुख-दुख में साथ खड़े रहते थे। उन्होंने कहा कि सुदिव्य सोनू का अधूरा सपना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सभी लोग मिलकर पूरा करेंगे। साथ ही उन्होंने डॉक्टरों और आम लोगों से अपील की कि किसी भी बीमारी को छिपाना नहीं चाहिए, क्योंकि बीमारी के गंभीर होने पर स्थिति संभालना मुश्किल हो जाता है। वहीं एसएनएमएमसीएच के सर्जिकल आईसीयू में बिजली नहीं रहने से महिला की मौत के सवाल पर मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है और मीडिया में इसका दुष्प्रचार किया जा रहा है। हालांकि उन्होंने साफ कहा कि अगर अस्पताल में किसी भी तरह की लापरवाही सामने आती है तो दोषी किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। मंत्री ने कहा कि धनबाद की स्वास्थ्य व्यवस्था पिछले 20 वर्षों से खराब रही है और उनके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि पांच साल में पूरी व्यवस्था को चमत्कारिक तरीके से बदल दें।

# नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा से गंगा एक्सप्रेसवे की दूरी होगी कम, 30 से 45 मिनट का समय ही लगेगा

**लखनऊ,एजेंसी।** नोएडा इंटरनेशनल जेवर एयरपोर्ट जन सामान्य को समर्पित होने के बाद माल वाहन और यात्री आवागमन के दबाव को देखते हुए ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा ग्रेटर नोएडा महायोजना 2041 में संशोधन करते हुए माल वाहन और यात्री आवागमन को अलग अलग करने की योजना बनाई गई है। जिस पर सोमवार को पिकअप भवन सभागार लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विकास आलोक कुमार भी मौजूद रहे।

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा से गंगा एक्सप्रेसवे की दूरी को कम करते हुए 30 से 45 मिनट मिनट में ही पूरी करने के लिए हापुड़ बाईपास तक 105 मीटर चौड़ी सड़क बनाने की योजना है। कनेक्टिविटी को लगभग 15 किलोमीटर और आगे बढ़ाने से ग्रेटर नोएडा गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगा। इससे गंगा एक्सप्रेसवे तक यात्रा का समय घटकर 30 से 45 मिनट हो जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि लॉजिस्टिक हब से जेवर हवाई अड्डे तक 06 लेन की एलिवेटेड सड़क भी बनाए जाने की योजना है। ग्रेटर नोएडा में एमएमएलएच और एमएमटीएच प्रमुख आगामी परियोजनाएं हैं, जिनसे शहर में माल ढुलाई में तेजी आएगी। इससे लॉजिस्टिक्स हब से हवाई अड्डे तक यातायात की आवाजाही आसान होगी और क्षेत्र के औद्योगिक विकास को मजबूती मिलेगी। मंत्री नन्दी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में नए भारत का नया उत्तर प्रदेश आज हर क्षेत्र में प्रगति के राह पर अग्रसर है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा आज उत्तर प्रदेश का मुकुट बन कर उभरा है। जहां तीव्र गति से विकास हो रहा है। इसलिए उद्योग, व्यापार और आम जन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जन उपयोगी योजनाएं बनाए जाने की आवश्यकता है। जिसके लिए हमारी डबल इंजन की सरकार तत्पर है। लॉजिस्टिक हब से वेर्स्टन डेडीकेटेड फेट कोरीडोर के समानान्तर 06 लेन की ऐलीवेटेड सडक नियोजित की जानी प्रस्तावित है, जिसका संरेखण महायोजना में अंकित करते हुए जेवर ऐयरपोर्ट से जोड़ा जाना प्रस्तादित है। जहाँ लॉजिस्टिक हब से सामान सीधा एयर कार्गो टर्मिनल तक पहुँच सके।

# विधायक पुत्र से छात्रों ने की मारपीट, जांच में जुटी पुलिस

**रांची,एजेंसी।** शहर के धुर्वा थाना क्षेत्र में एमिटी यूनिवर्सिटी के मेन गेट के बाहर सोमवार को शराब के नशे में छात्रों के दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हो गई। इस विवाद के दौरान लोजपा विधायक जनार्दन पासवान के पुत्र सौरभ पासवान भी मौके पर मौजूद थे। घटना के बाद विधायक की ओर से पुत्र के अपहरण की सूचना पुलिस को दिए जाने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और नये विधानसभा के पास से विधायक पुत्र को सकुशल बरामद कर लिया।

पुलिस के मुताबिक विधायक पुत्र ने भी शराब पी रखी थी। रांची सिटी एसपी पारस राणा ने प्रत्यक्षदर्शियों के हवाले से बताया कि एमिटी यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र मेन गेट के बाहर शराब पी रहे थे। इसी दौरान छात्रों के दूसरे गुट से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते कहासुनी ने मारपीट का रूप ले लिया। दोनों गुटों के बीच जमकर हाथापाई हुई। बताया जा रहा है कि इस दौरान सौरव पासवान के साथ भी मारपीट की गई। सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि लोजपा विधायक जनार्दन पासवान ने फोन कर अपने पुत्र के अपहरण की सूचना दी थी। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम को तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना किया गया। पुलिस ने मौके पर मौजूद लोगों से पूछताछ की और घटनाक्रम की जानकारी जुटाई।सिटी एसपी ने बताया कि शुरुआती जांच में सामने आया है कि छात्रों के दूसरे गुट के युवक सौरभ पासवान को अपनी गाड़ी में बैठाकर ले गए थे। बाद में उन्हें नई विधानसभा के पास रास्ते में उतार दिया गया। पुलिस ने सौरभ पासवान को रिकवर कर थाने पहुंचाया। सिटी एसपी पारस राणा ने कहा कि शुरुआती जांच में मामला अपहरण का नहीं लग रहा है। प्रथम दृष्टया जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक पूरी घटना शराब के नशे में छात्रों के बीच हुए विवाद और मारपीट से जुड़ी है। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक, सौरभ पासवान के साथ मारपीट करने वाले युवकों की पहचान कर ली गई है। पुलिस उनकी भूमिका की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। सिटी एसपी ने कहा कि एफआईआर के आधार पर मामले में विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच में जुटी है। यूनिवर्सिटी गेट के बाहर शराब पीने और उसके बाद छात्रों के बीच हुए विवाद ने सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।

# योगी सरकार अल्पसंख्यकों के हितों के लिए कर रही कार्य : दानिश आजाद अंसारी

**लखनऊ,एजेंसी।** राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग (एनसीएमईआई) भारत सरकार एवं अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग, उत्तर प्रदेश के संयुक्त तत्वाधान में सोमवार को इन्दिरा भवन लखनऊ के सभागार कक्ष संख्या-511 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में ''अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों की राष्ट्र निर्माण में भूमिका-विकसित भारत, 2047'' के परिप्रेक्ष्य में बैठक आयोजित की गयी।

बैठक में प्रो. (डा.) शाहिद अख्तर, कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग (एनसीएमईआई) भारत सरकार, मुख्य अतिथि उप्र सरकार में राज्यमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण, वक्फ एवं हज विभाग दानिश आजाद अन्सारी, अल्पसंख्यक कल्याण उप्र के निदेशक शीलधर सिंह यादव, विभिन्न शैक्षिक विभागों के अधिकारी तथा जनपद लखनऊ की विभिन्न अल्पसंख्यक संस्थाओं के प्रतिनिधिगण उपस्थित रहे। बैठक को सम्बोधित करते हुए प्रो. (डा.) शाहिद अख्तर कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग (एनसीएमईआई) ने एनसीएमईआई के कार्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि एनसीएमईआई अल्पसंख्यक संस्थाओं के हितों एवं अधिकारों के संरक्षण के लिए लगातार कार्य कर रही है। अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त करने के लिए सम्बन्धित विभागों के उच्चाधिकारियों के साथ हुई बैठक में उनके द्वारा प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए निर्देशित किया जा चुका है। कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा संस्थाओं से यह भी अपेक्षा की गयी कि वह विकसित भारत 2027 विजन के सम्बन्ध में अपनी संस्था स्तर पर आयोजित विभिन्न प्रोग्रामों/सेमिनारों तथा भविष्य के प्रस्तावित कार्यक्रमों के सम्बन्ध में विस्तृत रिपोर्ट 15 दिन के भीतर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के माध्यम से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग को प्रेषित करने की कार्यवाही की जाए। संस्था स्तर पर विकसित भारत 2047 की कार्ययोजना बनाकर विजन के कार्यान्वयन के लिए कार्य/दायित्व का निर्धारण सुनिश्चित किया जाए तथा आवश्यकतानुसार संस्थाओं द्वारा अनुभव की जाने वाली समस्याओं के बारे में सुझाव भी प्रस्तुत किये जाएं। भविष्य में राज्य/जोन स्तर पर अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं के साथ मींटिग की जायेगी। सस्थाओं से समन्वय तथा सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के द्वारा एक ई-मेल/डिजिटल प्लेटफार्म उपलब्ध कराया जायेगा। राज्यमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ, हज विभाग दानिश आजाद अन्सारी ने सम्बोधित करते हुए कहा कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग एवं उप्र सरकार अल्पसंख्यकों के हितों के लिए लगातार कार्य कर रही है।

# उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह ने दुबई में बिहार पवेलियन का किया उद्घाटन, निवेश के अवसरों को किया प्रदर्शित

**पटना,एजेंसी।** मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार ने वैश्विक निवेश के लिए अपनी पहुंच को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आयोजित वार्षिक निवेश बैठक (एआईएम) कांग्रेस 2026 में बिहार पवेलियन का उद्घाटन सोमवार को किया गया। पवेलियन के माध्यम से वैश्विक निवेशकों के समक्ष बिहार की औद्योगिक क्षमता, निवेश के अवसरों और राज्य में किए जा रहे निवेशक-अनुकूल सुधारों को प्रदर्शित किया जा रहा है। बिहार सरकार की उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह ने उद्योग विभाग के सचिव कुंदन कुमार, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में बिहार पवेलियन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने राज्य के तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक इकोसिस्टम और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में उभर रहे निवेश अवसरों की जानकारी दी।

श्रेयसी सिंह ने निवेश प्रक्रिया को सुगम बनाने तथा वैश्विक व्यवसायों के साथ मजबूत साझेदारी स्थापित करने के प्रति बिहार सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि एआईएम कांग्रेस में बिहार की सहभागिता का उद्देश्य सार्थक साझेदारियां स्थापित करना और निवेशकों की रुचि को राज्य में ठोस निवेश अवसरों में परिवर्तित करना है। बिहार पवेलियन में राज्य के औद्योगिक बुनियादी ढांचे, निवेश की संभावनाओं, विभिन्न क्षेत्रों की क्षमताओं, नीतिगत प्रोत्साहनों तथा निवेशक-अनुकूल सुधारों को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जा रहा है। इसके माध्यम से आगंतुकों और संभावित निवेशकों को बिहार के तेजी से बदलते औद्योगिक परिदृश्य तथा विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध अवसरों की जानकारी दी जा रही है। पवेलियन में प्रमुख रूप से बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पैकेज, 2025, बिहार सेमीकंडक्टर पॉलिसी, 2026, बिहार ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) पॉलिसी, 2026, बिहार टेक्सटाइल एंड लेदर पॉलिसी (संशोधित), 2022, बिहार टूरिज्म पॉलिसी और आईटी पॉलिसी सहित अन्य नीतियों को प्रदर्शित किया जा रहा है। इसके अलावा राज्य में लगातार विस्तारित हो रहे औद्योगिक लैंड बैंक, प्लग-एंड-प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर होती कनेक्टिविटी तथा निवेश और औद्योगिक विकास को गति देने वाले व्यापक नीतिगत इकोसिस्टम को भी पवेलियन में प्रमुखता से प्रस्तुत किया जा रहा है। बिहार सरकार का प्रयास है कि अंतरराष्ट्रीय निवेशकों और वैश्विक कारोबारी समूहों को राज्य में उपलब्ध संभावनाओं से अवगत कराया जाए तथा उन्हें निवेश के लिए अनुकूल वातावरण की जानकारी दी जाए। एआईएम कांग्रेस जैसे वैश्विक मंच पर बिहार की औद्योगिक एवं नीतिगत क्षमताओं का प्रदर्शन राज्य को अंतरराष्ट्रीय निवेश मानचित्र पर और मजबूती से स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

### एआईएम कांग्रेस 2026 में निवेश अवसरों, नीतिगत प्रोत्साहनों और औद्योगिक इकोसिस्टम को किया जा रहा प्रदर्शित

# निवेशकों का भरोसेमंद साथी है मध्य प्रदेश : मोहन यादव

**भोपाल,एजेंसी।** मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि दुबई से हमारे सहज और स्वाभाविक संबंध हैं। हम दुबई के भरोसेमंद साथी हैं और संभावनाओं और अवसरों की सौगात लेकर दुबई के साथ खड़े हैं। हमारी नीति, नीयत, नेतृत्व और पूरी सरकार निवेशकों के स्वागत के लिए तैयार है। निवेशक बिना किसी संकोच के मध्य प्रदेश में निवेश करें। हमारी सरकार आपको कभी भी निराश नहीं होने देगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव सोमवार को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) प्रवास के दूसरे दिन सोमवार को दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर में हो रही एआईएम कांग्रेस-2026 के दौरान विशेष रूप से आयोजित 'इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन : मध्य प्रदेश' सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश अतुल्य भारत का दिल है और हम दुबई के सभी निवेशकों के दिल में जगह बनाने आए है। उन्होंने निवेशकों से कहा कि मध्य प्रदेश की औद्योगिक नीतियां बेहद पारदर्शी और निवेशक अनुकूल हैं।

सत्र में यूएई के फॉरेन ट्रेड मिनिस्टर डॉ. थानी बिन अहमद अल जेयूदी, यूएई में भारत के उच्चायुक्त डॉ. दीपक मित्तल सहित बड़ी संख्या में देश-विदेश के उद्योगपति, इन्वेस्टर्स और इंडस्ट्री पार्टनर उपस्थित थे। सत्र के दौरान मध्य प्रदेश में हो रही औद्योगिक प्रगति, यहां की खूबियों, निवेश अवसरों और अनंत संभावनाओं पर केंद्रित एक ऑडियो-वीडियो फिल्म (एवी) का प्रदर्शन भी किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुबई वैश्विक निवेश और नवाचार का केंद्र है। मध्य प्रदेश के लिए गर्व का विषय है कि आज वैश्विक साझेदारी, रणनीतिक और आर्थिक सहयोग, मजबूत और

समृद्ध भविष्य का साझा रोडमैप एआईएम कांग्रेस के इस बड़े प्लेटफॉर्म पर रखा गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश देश-विदेश के सभी निवेशकों को दीर्घकालिक और विश्वस्तरीय साझेदारी के लिए नये अवसर उपलब्ध करा रहा है। भारत के सभी राज्यों में विकास की स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के बीच मध्यप्रदेश उन अग्रणी राज्यों में शामिल है, जो अपनी पारदर्शी नीतियों और आकर्षक योजनाओं के आधार पर औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करता है। दुनिया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए गंतव्यों की तलाश चल रही है। ऐसे समय में मध्य प्रदेश निवेशकों और उद्योग समूहों को सभी सुगम अवसर उपलब्ध करा रहा है। नीति, नीयत और निवेश में मध्य प्रदेश ने निवेशकों का दिल जीता है। मध्यप्रदेश, देश का वह प्रदेश है, जिसने निवेशकों को आगे बढ़ने के लिए अवसर वर्तमान के सभी सेक्टर्स में अवसर उपलब्ध कराए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में प्रचुर प्राकृतिक और कुशल मानव संसाधन हैं। मध्य प्रदेश ने अपनी उद्योग अनुकूल नीतियों, तेजी से विकसित हो रही औद्योगिक अधोसंरचनाओं और दिनों-दिन बढ़ती अर्थव्यवस्था से देश में अपना एक अलग ही स्थान बनाया है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश भारत का हृदय प्रदेश है, जिसकी कनेक्टिविटी देश के सभी राज्यों से बेहतर है। मध्य प्रदेश 24 घंटे माल परिवहन की सुविधा प्रदान करता है। एक्सपोर्ट और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए राज्य सदैव अनुकूल है। देश में प्रमुख औद्योगिक केंद्र और बाजार तक पहुंच है, दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर, रेल नेटवर्क, आधुनिक लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर आदि सुविधाओं के कारण मध्य प्रदेश का विशेष स्थान बना है। कृषि, उद्योग, सेवाएं, नई औद्योगिक आधारित अर्थव्यवस्थाओं का केंद्र है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार निवेशकों के लिए हर संभव कदम उठाने के लिए तैयार है। मध्यप्रदेश कृषि, फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल्स, फॉर्मास्युटिकल्स, इंजीनियरिंग, लॉजिस्टिक्स, रिन्युएबल एनर्जी, डिजिटल टेक्नोलॉजी और व्यापार की अपार संभावनाओं वाला राज्य है। राज्य को सभी क्षेत्रों में आगे लाकर यहां निवेश बढ़ाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत भविष्य की संभावनाओं वाला देश बन रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के कालखंड में भारत सबसे समृद्ध अर्थव्यवस्था वाला देश बना है, दुबई और अन्य सभी खाड़ी देशों से हमारे अच्छे संबंध हैं। यूएई के फॉरेन ट्रेड मिनिस्टर डॉ. थानी ने कहा कि जुलाई 2025 में यूएई और मध्य प्रदेश के बीच व्यापार और व्यवसाय में सहयोग बढ़ाने पर अहम चर्चा हुई थी। भारत अर्थव्यवस्था की दृष्टि से हमारा एक पुराना और महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार है। पिछले साल भारत और यूएई का द्विपक्षीय तेल व्यापार 100 बिलियन डॉलर रहा। दोनों देश मिलकर द्विपक्षीय व्यापार को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके साथ निवेश और नागरिकों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ बना रहे हैं। मुझे विश्वास है कि मध्य प्रदेश हमारी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएगा। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, जहां प्राकृतिक संसाधनों और स्किल्ड मैन पॉवर की कोई कमी नहीं है। यूएई मध्य प्रदेश की क्षमताओं को रेखांकित करता है।

# मराठा आरक्षण : मनोज जरांगे का 12 सितंबर को जालना में बैठक के बाद मुंबई कूच का ऐलान

**मुंबई,एजेंसी।** मराठा आरक्षण के लिए पिछले दस दिनों से भूख हड़ताल कर रहे मराठा नेता मनोज जारांगे पाटिल ने सोमवार को कहा कि 12 सितंबर को अंतरावली सराटी में एक महत्वपूर्ण बैठक होगी और इसके बाद मुंबई जाने की तारीख तय की जाएगी। मनोज जारांगे ने मराठा समाज से अपील की है कि फिलहाल कोई भी मुंबई की ओर न जाए।

जारांगे पाटिल ने सोमवार को जालना जिले के अंतरवाली सराटी में कहा कि राज्य सरकार उनके आंदोलन पर सुस्ती बरत रही है। उन्होंने दावा किया कि सरकार के रवैये से मराठा समाज में गुस्सा बढ़ रहा है। साथ ही उन्होंने शिंदे और फडणवीस सरकार पर मराठा समाज को धोखा देने का आरोप लगाया। उन्होंने महाराष्ट्र के अलग-अलग जिलों के मराठा समाज के लोगों से 12 सितंबर को अंतरावली सराटी पहुंचने की अपील की है। उन्होंने सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, मुंबई, नवी मुंबई, नागपुर, कोल्हापुर, नांदेड़, सांगली, सतारा, हिंगोली, परभणी, लातूर, धाराशिव, बीड, जालना और संभाजीनगर समेत कई इलाकों के लोगों से बैठक में शामिल होने को कहा। उन्होंने कहा कि बैठक के लिए अंतरावली में साउंड सिस्टम, एलईडी स्क्रीन और बैठने की व्यवस्था की जाएगी। चाहे बैठक में 10 लोग आएं, 50 लोग, 5 हजार या 5 लाख आएं आगे का फैसला वहीं लिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि मुंबई जाने की तारीख 12 सितंबर की बैठक के बाद तय की जाएगी।

उन्होंने मराठा समाज से फिलहाल अंतरावली में एकजुट होने और बैठक के बाद ही मुंबई की ओर आगे बढ़ने की अपील की है। उन्होंने आंदोलन के दौरान किसी मराठा आंदोलनकारी के घायल होने की स्थिति में महाराष्ट्र बंद की भी बात कही है। उन्होंने कहा कि मुंबई जाते समय पुलिस की ओर से किसी तरह की कार्रवाई या हमला हुआ तो स्थिति बिगड़ सकती है। उन्होंने आंदोलनकारियों से अपील करते हुए कहा कि किसी भी स्थिति में भगदड़ न मचाएं और संयम बनाए रखें। उन्होंने यह भी कहा कि उनका संघर्ष पुलिस से नहीं, बल्कि सरकार से है।

मुद्रक, प्रकाशक, स्वामी, सैफुल्लाह सिद्दिकी द्वारा आरडी प्रिंटिंग एंड पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, ए-24, सेक्टर-08, नोएडा (यूपी), से छपवा कर एन-81, बटला हाउस, जामिया नगर पुलिस स्टेशन, जामिया नगर, नई दिल्ली-110025 से प्रकाशित किया। सर्वाधिकार सुरक्षित, किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र दिल्ली होगा। (संपादक- सैफुल्लाह सिद्दिकी)